साप्ताहिक

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

RNI-MPHIN/2015/72544

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार 01-07 अगस्त 2022, वर्ष-8, अंक-17

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठ :-8, मूल्य :- 2 रुपए

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा

देशभर के सिर्फ 50 प्रतिशत किसानों को ही मिल पाया लाभ

मप्र में सिर्फ 12% कृषि कर्जमाफी

अरविंद मिश्र। भोपाल

अलग-अलग राज्यों में किसानों को कर्ज से मुक्त करने के लिए चलाई गई कृषि कर्जमाफी योजनाओं से देश के कितने किसानों को फायदा हुआ। इसे समझने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की गई है। इसमे खुलासा हुआ है कि सिर्फ देश के 50 फीसदी किसानों को ही इसका लाभ मिल पाया है। देश में किसानों को कर्ज के बोझ से राहत दिलाने वाली कृषि कर्ज माफी योजना काफी चर्चा में रही है। यह दावा किया जाता है कि अधिकांश किसानों को कर्जमाफी योजना का लाभ मिला। लेकिन, एक ताजा रिपोर्ट में इस योजना को लेकर जो खुलासा हुआ है उससे इसकी सफलता पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

क्योंकि इस रिपोर्ट दावा किया गया है कि देश के महज 50 फीसदी किसानों को ही कृषि ऋण माफी योजना का लाभ मिल पाया है। भारतीय स्टेट बैंक के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक अध्ययन के मुताबिक 2014 के बाद से जिन 9 राज्यों में कृषि ऋण माफी का एलान किया गया था, उन राज्यों में कर्ज माफी की इच्छा रखने वालों में से केवल आधे लोगों को ही इसका लाभ मिल पाया। कर्ज माफी योजना में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक और तेलंगाना शामिल हैं। तेलंगाना में (5 फीसदी), मध्यप्रदेश में 12 फीसदी, पंजाब में 24 फीसदी, झारखंड में 13 फीसदी, पंजाब में 24, उत्तर प्रदेश में 52 फीसदी और कर्नाटक में 38 फीसदी लोगों को योजना का लाभ मिला है। जबकि 2018 में छत्तीसगढ़ में 100 फीसदी पात्र किसान और 2020 में महाराष्ट्र द्वारा 91 फीसदी पात्र किसानों को ऋण माफी योजना का लाभ मिला।

पात्रता वाले अधिकांश खाते मानक श्रेणी के

कर्ज माफी की पात्रता रखने वाले अधिकांश खाते मानक श्रेणी के थे। इससे यह सवाल खड़ा होता है, क्या वाकई लोन माफी जरूरी थी। मानक खाता उन खातों को कहा जाता है जिसमें उधारकर्ता सही समय से अपना ऋण चुका रहा रहा होता है। जबकि ऐसे खातों को भी कृषि ऋण माफी योजना के तहत कवर किया गया। ऐसे खातों की संख्या विशेष रूप से झारखंड (100 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (96प्रतिशत), आंध्र प्रदेश (95 प्रतिशत), पंजाब (86 प्रतिशत), तेलंगाना (84 प्रतिशत) थी।

लक्ष्य से भटकी योजना

कर्ज माफी योजना के तहत आंध्र प्रदेश के 42 लाख किसानों में से 92 फीसदी किसान लाभ के पात्र थे। जबकि तेलंगाना में यह संख्या पांच फीसदी थी। 2014 से 2022 तक लगभग 3.7 करोड़ पात्र किसानों में से मात्र 50 फीसदी को ही ऋण माफी का लाभ मिला। जिन किसानों को लक्ष्य करके ऋण माफी योजना चलाई गई थी उन किसानों तक लाभ पहुंचा ही नहीं। रिपोर्ट में यह चिंता भी जताई गई है कि क्या वाकई आर्थिक संकट के दौर में किसानों को इससे फायदा मिलता है।

असली किसानों को पैसा मिला या नहीं

महाराष्ट्र के किसानों को ऋण माफी का लाभ देने के लिए 34000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई थी। देश के 9 राज्यों में ऋण माफी योजना को लेकर यह योजना 2014 में लागू की गयी थी। शोध में यह पता लगाने का प्रयास किया गया कि 2.25 लाख करोड़ रुपए असली किसानों को मिले या नहीं।

नुकसानदायक कर्ज माफी कल्चर

रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि ऋण माफी कल्चर आने वाले समय में किसानों के हितों को नुकसान पहुंचा सकती है। इसके साथ ही इसका असर किसानों और कृषि के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने पर भी पड़ता है, क्योंकि इस तरह से सरकारों पर पड़ने वाला वित्तीय बोझ संस्थानों को खोंखला कर सकता है।

देरी और फिर लगातार बारिश की वजह से घटा रकबा

प्रदेश में छह लाख हेक्टेयर कम हुई धान की बोवनी

भोपाल। जागत गांव हमार

प्रदेश में पहले वर्षा में विलंब और फिर लगातार पानी गिरने के कारण इस वर्ष धान की बोवनी प्रभावित हुई है। जबलपुर, कटनी, बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर, ग्वालियर, शिवपुरी सहित अन्य जिलों में बोवनी 50 प्रतिशत से भी कम है। नरसिंहपुर में तो कम वर्षा के कारण किसानों ने नलकूप से खेतों में पानी भरकर बोवनी की। अभी तक 13.77 लाख हेक्टेयर में ही बोवनी हुई है। यह पिछले साल इस अवधि में हुई बोवनी से छह लाख हेक्टेयर कम है। हालांकि, मक्का, बाजारा और ज्वार की बोवनी जरूर लक्ष्य के अनुरूप हो चुकी है। सोयाबीन 49.79 और उड़द की बोवनी 12.83 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है। प्रदेश में वर्ष 2022 में 147 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ फसल की बोवनी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। धान के लिए 34 लाख 71 हजार हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया है। पिछले साल 22 जुलाई तक 19.83 लाख हेक्टेयर में बोवनी हो गई थी लेकिन इस बार यह 13.77 लाख हेक्टेयर में ही हो पाई।

यहां के किसान भी नहीं कर पाए बोवनी

धान के प्रमुख क्षेत्र कटनी व बालाघाट में 14 और नरसिंहपुर में 27 प्रतिशत बोवनी हुई। सिंगरौली, सतना और दतिया में 11, बुरहानपुर में 18 प्रतिशत ही लक्ष्य की पूर्ति हुई है। जबकि, सीहोर, विदिशा, हरदा, अशोकनगर, गुना और झाबुआ में धान की सौ प्रतिशत बोवनी हो चुकी है। उधर, सोयाबीन की बोवनी भी पिछले साल से एक लाख हेक्टेयर में कम हुई है। वर्ष 2021 में 22 जुलाई तक 49.76 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन की बोवनी हुई थी, जो इस वर्ष 48.76 लाख हेक्टेयर है।

- सरकार ने 54.42 लाख हेक्टेयर में बोवनी का लक्ष्य रखा है। मक्का 15 लाख हेक्टेयर में बोया जा चुका है तो बाजरा दो लाख 36 हजार हेक्टेयर में लगाया गया है। तुअर के लिए चार लाख 43 हजार हेक्टेयर क्षेत्र निर्धारित किया गया है। इस वर्ष अभी तक 111.51 लाख हेक्टेयर में बोवनी हो चुकी है।

  अजीत केसरी, अपर मुख्य सचिव कृषि

- वर्षा का दौर थमते ही बोवनी की गति बढ़ जाएगी। अगस्त के दूसरे पखवाड़े तक बोवनी होती है, इसलिए अभी चिंता की बात नहीं है। मक्का, उड़द, सोयाबीन सहित अन्य फसलों की बोवनी ठीक हो गई है।

  जीएस कौशल, पूर्व कृषि संचालक

समर्थन मूल्य पर कब होगी खरीदी पता नहीं

किसानों के लिए इस साल घाटे का सौदा रही मूंग

भोपाल। जागत गांव हमार

प्रदेश में ग्रीष्मकाल में मूंग पैदा करने वाले किसान इस बार व्यापारियों के यहां औने-पौने दामों में मूंग बेचने को मजबूर हैं। सरकार के घटिया सिस्टम की वजह से इस बार मूंग को समर्थन मूल्य पर खरीदने की तारीखों का ऐलान भी नहीं किया गया है। हालांकि मूंग खरीदी के लिए पंजीयन जरूर किया जा रहा है। मूंग की फसल जून के पहले पखवाड़े में ही बिकने के लिए तैयार हो चुकी थी। लेकिन इस बीच सरकार ने न तो समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू की और न ही खरीदी की तारीखों का ऐलान किया। मजबूरी में किसानों ने व्यापारियों को 4500 रुपए क्विंटल में ही फसल बेच दी। इस बार मूंग का समर्थन मूल्य 7225 रुपए प्रति क्विंटल है। जिन किसानों ने मूंग बचाकर रखा है। वे अब चिंतित हैं। बारिश लगातार जारी है। ऐसे में घर से मूंग निकालकर खरीद केंद्र ले जाना मुश्किल है।

मंत्री ने की घोषणा: 3.67 रुपए प्रति यूनिट बिजली खरीदेगी सरकार

बिजली की खेती कर रहा सागर का किसान

अनिल दुबे। सागर

अभी तक आपने खेतों में अनाज, सब्जी और फलों की खेती होती देखी होगी पर क्या आपको पता है खेतों में बिजली की खेती भी हो सकती है। जी हां मध्य प्रदेश के सागर जिले में गढ़ाकोटा में एक किसान ने खेत में बिजली ही पैदा कर दी। बिजली उत्पादन के बाद सबसे बड़ा सवाल था कि उसे कौन खरीदेगा, तो किसान की समस्या प्रदेश सरकार ने खत्म कर दी। प्रदेश सरकार ने के मंत्री गोपाल भार्गव ने घोषणा कर बिजली खरीदने का रेट भी बता दिया। मंत्री ने कहा कि किसान की बिजली सरकार 3.67 रुपए प्रति यूनिट बिजली खरीदेगी। दरअसल, गड़ाकोटा के नटराज ऑडिटोरियम में ऊर्जा विभाग एवं एनटीपीसी विभाग के संयुक्त कार्यक्रम में आजादी के 75 वर्ष के अमृत महोत्सव के अवसर पर उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य कार्यक्रम हुआ। जिसमें प्रदेश सरकार के लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव भी मौजूद थे। मंत्री भार्गव ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रत्येक वर्ष 22 हजार करोड़ रुपए की किसानों के लिए सब्सिडी प्रदान कर बिजली उपलब्ध करा रही है। बिजली के बिना हमारा जीवन अधूरा है इसे बचाने की हर संभव प्रयास कर समय पर बिजली बिलों को अदा करें, क्योंकि बिजली और प्रगति एक दूसरे के पूरक है।

खेतों में सौर ऊर्जा विभाग के माध्यम से सोलर पैनल लगाएं

मंत्री गोवाल भार्गव ने बताया कि खेतों में सौर ऊर्जा विभाग के माध्यम से सोलर पैनल लगाएं। जिससे उनको 24 घंटे बिजली उत्पन्न होगी और और अपनी खेती करने के साथ-साथ अधिक बिजली को 3.67 रुपए प्रति यूनिट की दर से सरकार को विक्रय भी कर सकेंगे। सौर ऊर्जा विभाग के माध्यम से सोलर पैनल लगवाने के लिए विभाग ने को कुसुम अ एवं कुसुम स योजना प्रारंभ की है। जिसमें सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है। इसकी जानकारी अधीक्षण अभियंता योगेश सिंघई ने योजना के बारे में विस्तार जानकारी दी।

एक अगस्त से किसान एमपीकिसान एप पर दर्ज करा सकेंगे अपनी फसल की जानकारी

अब किसान खुद करेंगे अपनी फसल की गिरदावरी

मेरी गिरदावरी-मेरा अधिकार कृषि

भोपाल। जागत गांव हमार

आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश और आत्म-निर्भर किसान के मंत्र पर राज्य सरकार ने एक और किसान हितैषी निर्णय लिया है। मेरी गिरदावरी- मेरा अधिकार में अब किसान निश्चिंत होकर अपनी फसल की जानकारी एम पीकिसान एप के माध्यम से दर्ज कर सकेंगे। इस जानकारी का उपयोग फसल हानि, न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना, भावांतर योजना, किसान क्रेडिट कार्ड और कृषि ऋण में किया जायेगा। किसान अपनी फसल की जानकारी एक अगस्त से 15 अगस्त 2022 तक दर्ज करा सकते हैं। किसान की इस जानकारी का आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस एवं पटवारी से सत्यापन होगा।

एप में किसानों के लिए कई सुविधाएं

मेरी गिरदावरी-मेरा अधिकार में किसान को यह सुविधा उपलब्ध करवाई गई है कि वे अपने खेत से ही स्वयं फसल की जानकारी एमपीकिसान एप पर दर्ज कर अपने आप को रजिस्टर सकते हैं। इस एप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। किसान एप पर लॉगिन कर फसल स्व-घोषणा, दावा आपत्ति आप्शन पर क्लिक कर अपने खेत को जोड़ सकते हैं। खाता जोड़ने के लिये प्लस ऑप्शन पर क्लिक कर जिला/तहसील/ग्राम/खसरा आदि का चयन कर एक या अधिक खातों को जोड़ा जा सकता है। खाता जोड़ने के बाद खाते के समस्त खसरा की जानकारी एप में उपलब्ध होगी। उपलब्ध खसरा की जानकारी में से किसी भी खसरे पर क्लिक करने पर ए आई के माध्यम से जानकारी उपलब्ध होगी। किसान के सहमत होने पर एक क्लिक से फसल की जानकारी को दर्ज किया जा सकेगा। संभावित फसल की जानकारी से असहमत होने पर खेत में बोयी गई फसल की जानकारी खेत में उपस्थित होकर लाइव फोटो के साथ दर्ज की जा सकती है।

मुख्यमंत्री की किसानों से अपील

सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हित के प्रति प्रतिबद्ध है। उन्होंने प्रदेश के किसानों से अपील की है कि वे मेरी गिरदावरी-मेरा अधिकार में अपनी फसल को एमपीकिसान एप में अपलोड कर केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा मिलने वाली सुविधाओं का लाभ उठायें। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में किसान ई-गिरदावरी को अपनाने के लिये 15 अगस्त तक अपने आप को रजिस्टर कर सकेंगे।

आम की खेती करने वाला यह किसान है बेहद खास, एक ही पेड़ से उगा दी 300 वैराइटी, नाम रखा ऐश्वर्या, सचिन और नरेंद्र मोदी

किसान का कमाल, 120 साल पुराने पेड़ से तैयार की आम की करीब 300 किस्म

लखनऊ। जागत गांव हमार

आम की खेती के लिए दुनियाभर में मशहूर यूपी के मलीहाबाद में एक किसान ने 120 साल पुराने पेड़ से आम की करीब 300 किस्मों को पैदा किया है। मलीहाबाद में आम की खेती करने वाले कलीम उल्लाह खान बताते है कि सामान्य आंखों से देखने पर यह सिर्फ एक आम का पेड़ नजर आता है, लेकिन यह अपने आप में आम की पूरी यूनिवर्सिटी है और दुनिया का सबसे बड़ा आम का 'कॉलेज' है। 82 वर्षीय कलीम ने बताया कि बचपन में ही स्कूली शिक्षा छोड़कर आम की नई वैराइटी पैदा करने में जुट गए थे। शुरुआत में सात नई किस्म के पौधे तैयार किए, लेकिन एक आपदा में सभी नष्ट हो गए थे।

1987 से अब तक 300 प्रजातियां बनाईं- कलीम ने बताया कि इसके बाद भी हार नहीं मानी और 1987 से अब तक 120 साल पुराने आम के पेड़ से ही 300 तरह की अलग-अलग प्रजातियां विकसित कीं। इसमें सभी का रंग-रूप, आकार और स्वाद बिलकुल अलग है। 120 साल पुराना यह आम का पेड़ करीब 30 फीट का है और इसकी घनी शाखाएं आज भी सूरज की रोशनी को जमीन तक नहीं आने देतीं। कलीम ने कहा, इसकी छांव में बैठकर मैंने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी।

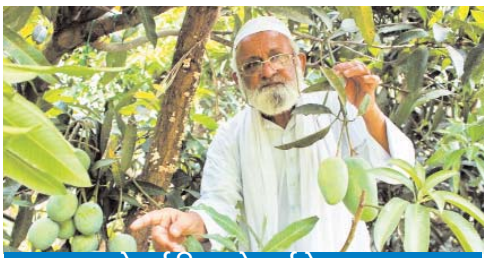

सबसे नई किस्म ऐश्वर्या के नाम पर

कलीम के अनुसार, आम की सबसे नई वैराइटी बॉलीवुड अभिनेत्री और 1994 की मिस वर्ल्ड विजेता ऐश्वर्या के नाम पर रखी गई है। यह अब तक की सबसे अच्छी वैराइटी भी साबित हो रही है। कलीम ने कहा, यह आम भी अभिनेत्री की तरह ही बेहद खूबसूरत है। इसका वजन भी एक किलोग्राम तक होता है। कलीम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में भी एक वैराइटी का नाम रखा है। इसके अलावा महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, अनारकली जैसे नामों की किस्में भी कलीम के बाग में हैं। उनका कहना है कि आदमी को आता है और चला जाता है, लेकिन आम हमेशा रहते हैं। लोग जब भी इस आम को खाएंगे अपने चहेते क्रिकेटर को याद करेंगे।

कोई भी वैराइटी एक समान नहीं: दावा है कि जिस तरह दो फिंगरप्रिंट एक जैसे नहीं होते, उसी तरह आम की दो वैराइटी भी एकसमान नहीं हो सकती है। इसके लिए दो किस्मों की कलम लगाकर नई किस्म तैयार की जाती है। दोनों कलम को साथ जोड़कर टेप से बांध दिया जाता है और अगले सीजन तक आम की नई वैराइटी तैयार हो जाती है।

कृषि अवसंरचना कोष में सर्वश्रेष्ठ मध्य प्रदेश को मिला सम्मान

भोपाल। मध्यप्रदेश को कृषि अवसंरचना कोष एवं सर्वश्रेष्ठ कार्य करने के लिये नई दिल्ली में पुरस्कृत किया गया।

मध्यप्रदेश ने वर्ष 2022 में प्रथम स्थान प्राप्त किया। एपी शिंदे हाल कृषि संस्थान पूसा नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर एवं कृषि राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी ने विभिन्न श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले राज्यों को सम्मानित किया। मध्यप्रदेश शासन की ओर से अपर मुख्य सचिव किसान-कल्याण एवं कृषि विकास श्री अजीत केसरी ने मध्यप्रदेश एआईएफ दल के साथ पुरस्कार प्राप्त किया।

कृषि क्षेत्र में करेंगे उन्नत तकनीक का इस्तेमालः प्रीति मैथिल

भोपाल। प्रदेश के किसानों को अधिकतम लाभान्वित करने के लिये कृषि क्षेत्र में उन्नत तकनीक का इस्तेमाल किया जायेगा। संचालक कृषि प्रीति मैथिल ने कृषि विभाग के पोर्टल की समीक्षा के लिये शुक्रवार को विभागीय एवं संबंधित संस्थाओं के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में यह बात कही। उन्होंने बताया कि किसान-कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा फसलों की स्थिति एवं उत्पादकता के सटीक और त्वरित आकलन के लिये सेटेलाईट डेटा तथा रिमोट सेसिंग तकनीक के उपयोग लिये एग्री जीआईएस पोर्टल बनवाया जा रहा है। पोर्टल निर्माण नेशनल रिमोट सेन्सिंग केंद इसरो तथा प्रदेश की तकनीकी संस्थाओं के समन्वय से हो रहा है। संचालक ने बताया कि सेटेलाईट डेटा तथा रिमोट सेसिंग तकनीक का उपयोग कर फसल क्षेत्रफल की प्रणाली विकसित की गयी है। इस वर्ष से पूर्णतया ई-गिरदावरी की जा रही है। किसानों को सुगमता एवं समय पर बीमा लाभ सुनिश्चित किये जाने हेतु भारत सरकार के फसल बीमा पोर्टल का भू-अभिलेख से इंटीग्रेशन किया गया है।

पौधरोपण के लिए अब परंपरागत तकनीक नहीं, अत्याधुनिक तकनीक का करेंगे उपयोग

जंगल और पर्यावरण बचाने के लिए तैयार है बीजबम

प्रवीण नामदेव। जबलपुर

जंगलों और पर्यावरण को बचाने के लिए अब मिट्टी की गेंद यानी सीडबॉल मदगार साबित होगी। जहां पौध रोपण के लिए पहुंच पाना मुश्किल है वहां यह गेंद अपना काम करेगी। कृषि विज्ञान केंद्र ने किसानों के साथ मिलकर इस तरह के मिट्टी के सीडबॉलों का निर्माण किया है। ऐसे करीब 10 हजार सीड बॉल का निर्माण किया गया है।

हर सीडबॉल में एक से दो बीज- हर सीडबॉल में 1 से 2 बीज रखे गए गए हैं। ताकि यदि एक बीज खराब भी हो जाए तो दूसरे से पौधा तैयार हो जाए। इन सीडबॉल

को बायोफर्टीलाइजर, गोबर खाद, काली मिट्टी के सम्मिश्रण के प्रयोग से तैयार किया जाता है। जब यह सीडबॉल जमीन में मिट्टी व पानी के संपर्क में आते ही बीजों को सुरक्षा कवच देते हुए बीजों को तेजी से अंकुरित करवी है।

पर्यावरण बचाने में निभा सकते हैं भूमिका- पर्यावरण को बचाने में इससे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। पौध रोपण के लिए सबसे जरूरी गड्ढा खोदना और फिर बीज में मिट्टी डालना है। लेकिन दुर्गम एवं पहुंच विहीन स्थलों, पहाड़ियों में यह संभव नहीं है। ऐसे में इन सीड बाल को दूर से फेंकने बस से काम चल जाता है। चाहे बस या फिर ट्रेन में सफर कर रहे हों तो रास्ते में पड़ने वाले पहाड़ी क्षेत्र ढ़लान वाले इलाके, बंजर भूमि, शासकीय भूमि, जंगल आदि में बस एक सीड बॉल फेंककर पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं।

दस हजार सीडबॉल का निर्माण- कृषि विज्ञान केंद के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ.एके सिंह के अनुसार हमने करीब दस हजार सीड बॉल का निर्माण किसानों की मदद से कराया है। साथ ही किसानों को भी ट्रेनिंग दी है। अगस्त के पहले सप्ताह तक इसे ऐसे स्थानों में पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं।

यह है स्थिति

मुनगा सीडबॉल	2300
नीम सीडबॉल	1400
शूबबूल सीडबॉल	3200
आंवला सीडबॉल	1800
नीबू सीडबॉल	900
जामुन सीडबॉल	2000

-रोग महामारी का रूप लेकर पशुओं को ग्रसित करता है

-दुग्ध उत्पादन होता है प्रभावित

-बारिश के मौसम में पशुओं में कई संक्रामक रोग फैलते हैं

-ठंडे मौसम में कम होती है तीव्रता में कमी आ जाती है

पशु में लम्पी स्किन डिजीज एलएसडी रोग

किसान इस तरह करें लम्पी स्किन डिजीज रोग की पहचान और उसका नियंत्रण

भोपाल। जागत गांव हमार

भारत दुनिया में सबसे बड़ा पशुपालक तथा दुग्ध उत्पादक देश है। 20वीं पशुगणना के अनुसार देश में गोधन की आबादी 18.25 करोड़ है, जबकि भैंसों की आबादी 10.98 करोड़ है। इस प्रकार दुनिया में भैसों की संख्या भारत में सर्वाधिक है। देश की एक बड़ी आबादी पशुपालन से जुड़ी हुई है, यदि कोई भी रोग महामारी का रूप लेकर पशुओं को ग्रसित करता है तो इसका सीधा असर उनके उत्पादन पड़ता है, जिसका सीधा असर पशुपालकों की आय पर पड़ता है। बारिश के मौसम में पशुओं में कई संक्रामक रोग फैलते हैं जिसमें लम्पी स्किन डिजीज भी एक है। लम्पी स्किन डिजीज (एलएसडी) या ढेलेदार त्वचा रोग वायरल रोग है, जो गाय-भैंसों को संक्रमित करता है। इस रोग से कभी-कभी पशुओं की मौत भी हो सकती है। पिछले दो वर्षों में यह रोग तमिलनाडु, कर्नाटक, ओडिशा, केरल, असम, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में देखा गया है। लम्पी स्किन डिजीज रोग को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे बहुत तेजी से फैलने वाले रोगों की सूची में रखा है। एलएसडी वायरस मच्छरों और मक्खियों जैसे कीटों से आसानी से फैलता है। इसके साथ ही यह दूषित पानी, लार एवं चारे के माध्यम से भी पशुओं को संक्रमित करता है। गर्म एवं नमी वाला मौसम इस रोग को और ज्यादा तीव्रता से फैलता है। ठंडा मौसम आने पर इस रोग की तीव्रता में कमी आ जाती है। एलएसडी, क्रेप्रीपांक्स वायरस से फैलता है। अगर एक पशु में संक्रमण हुआ तो दुसरे पशु भी इससे संक्रमित हो जाते हैं। यह रोग मच्छरों-मक्खियों एवं चारे के जरिए फैलता है। भीषण गर्मी और पतझड़ के महीनों के दौरान संक्रमण बढ़ जाता है क्योंकि मक्खियां भी अधिक हो जाती है। वायरस दूध, नाक- स्राव, लार, रक्त और लेक्रिमल स्राव में भी स्रावित होता है, जो पशुओं को खिलाने और पानी देने वाले कुंडों में संक्रमण का अप्रत्यक्ष स्रोत बनता है। यह रोग गाय का दूध पीने से बछड़ों को भी संक्रमित कर सकता है। संक्रमण के 42 दिनों तक वीर्य में भी वायरस बना रहता है। इस रोग का वायरस मनुष्य के लिए संक्रमणीय नहीं है।

पशुओं को इस रोग से बचाने के उपाय

» रोगी पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखना चाहिए, यदि फ़ार्म पर या नजदीक में किसी पशु में संक्रमण की जानकारी मिलती है, तो स्वस्थ पशु को हमेशा उनसे अलग रखना चाहिए।

» रोग के लक्षण दिखाने वाले पशुओं को नहीं खरीदना चाहिए, मेला, मंडी एवं प्रदर्शनी में पशुओं को नहीं ले जाना चाहिए।

» फार्म में कीटों की संख्या पर काबू करने के उपाय करने चाहिए, मुख्यत: मच्छर, मक्खी, पिस्सू एवं चिंचडी का उचित प्रबंध करना चाहिए।

» रोगी पशुओं की जांच एवं इलाज में उपयोग हुए सामान को खुले में नहीं फेंकना चाहिए एवं फालतू सामान को उचित प्रबंधन करके नष्ट कर देना चाहिए।

» यदि अपने फार्म पर या आसपास किसी असाधारण लक्षण वाले पशु को देखते हैं, तो तुरंत नजदीकी पशु अस्पताल में इसकी जानकारी देनी चाहिए।

» एक फार्म के श्रमिक को दुसरे फ़ार्म में नहीं जाना चाहिए, इसके साथ-साथ श्रमिक को अपने शरीर की साफ-सफाई पर भी ध्यान देना चाहिए। संक्रमित पशुओं की देखभाल करने वाले श्रमिक, स्वस्थ पशुओं से दूरी बनाकर रहें या फिर नहाने के बाद साफ कपड़े पहनकर स्वस्थ पशुओं की देखभाल करें।

» पूरे फार्म की साफ-सफाई का उचित प्रबंध होना चाहिए, फर्श एवं दीवारों को अच्छे से साफ करके एक दीवारों की साफ-सफाई के लिए फिनोल (2 प्रतिशत) या आयोडीनयुक्त कीटनाशक घोल (1:33) का उपयोग करना चाहिए।

» बर्तन एवं अन्य उपयोगी सामान को रसायन से कीटाणु रहित करना चाहिए। इसके लिए बर्तन साफ करने वाला डिटरजेंट पाउडर, सोडियम हाइपोक्लोराइड, (2-3 प्रतिशत) या कुआटर्नरी अमोनियम साल्ट (0.5 प्रतिशत) का इस्तेमाल करना चाहिए।

» यदि कोई पशु लम्बे समय तक त्वचा रोग से ग्रस्त होने के बाद मर जाता है, तो उसे दूर ले जाकर गड्ढे में दबा देना चाहिए।

» जो सांड इस रोग से ठीक हो गए हों, उनकी खून एवं वीर्य की जांच प्रयोगशाला में करवानी चाहिए। यदि नतीजे ठीक आते हैं, उसके बाद ही उनके वीर्य का उपयोग करना चाहिए।

» अभी तक इस रोग का टीका नहीं बना है, लेकिन फिर भी यह रोग बकरियों में होने वाले गोट पॉक्स की तरह के टीके से उपचारित किया जा सकता है। गाय-भैंसों को भी गोट पॉक्स का टिका लगाया जा सकता है एवं इसके परिणाम भी बहुत अच्छे मिलते हैं इसके साथ ही दूसरे पशुओं को रोग से बचाने के लिए संक्रमित पशु को एकदम अलग बांधे एवं बुखार और लक्षण के हिसाब से उसका इलाज करवाना चाहिए।

लम्पी स्किन डिजीज एलएसडी रोग के लक्षण

इस रोग से ग्रस्त पशु में 2-3 दिनों तक तेज बुखार रहता है। इसके साथ ही पूरे शरीर पर 2 से 3 सेमी की सख्त गांठें उभर आती हैं। कई अन्य तरह के लक्षण जैसे कि मुंह एवं श्वास नली में जख्म, शारीरिक कमजोरी, लिम्फनोड (रक्षा प्रणाली का हिस्सा) की सूजन, पैरों में पानी भरना, दूध की मात्रा में कमी, गर्भपात, पशुओं में बांझपन मुख्यत: देखने को मिलता है। इस रोग के ज्यादातर मामलों में पशु 2 से 3 हफ्तों में ठीक हो जाता है, लेकिन दूध में कमी लम्बे समय तक बनी रहती है। अत्यधिक संक्रमण की स्थिति में पशुओं की मृत्यु भी संभव है, जो कि 1 से 5 प्रतिशत तक देखने को मिलती है। एलएसडी को कई प्रकार के रोगों के साथ भ्रमित किया जा सकता है, जिसमें स्यूडो लंपी स्किन डिजीज (बोवाइन हर्पीसवायरस 2), बोवाइन पैपुलर स्टोमाडीकोसिस शामिल हैं। इसलिए इस रोग की पुष्टि प्रयोगशाला में उपलब्ध परीक्षणों के माध्यम से वायरस डीएनए या उसकी एंटीबॉडी का पता लगाकर करनी चाहिए।

इलाज के लिए इन बातों का रखें ध्यान

» यह रोग विषाणु से फैलता है, जिसके कारण इस रोग का कोई विशिष्ट इलाज नहीं है। संक्रमण की स्थिति में अन्य रोग से बचाव के लिए पशुओं का इलाज करना चाहिए।

» रोगी पशुओं का इलाज के दौरान अलग ही रखना चाहिए।

» रोगी पशुओं के बचाव के लिए जरूरत अनुसार एंटीबायोटिक दवाइओं का उपयोग किया जा सकता है।

» दवाइयों का उपयोग डॉक्टर की सलाह अनुसार ही करना चाहिए।

» यदि पशुओं को बुखार है, तो बुखार घटाने की दवाई दी जा सकती है।

» यदि पशुओं के ऊपर जख्म हो, तो उसके अनुसार दवाई लगानी चाहिए।

» पशुओं की खुराक में नरम चारा एवं आसानी से पचने वाले दाने का उपयोग करना चाहिए।

मध्य प्रदेश में सहकारिता नीति लागू की जाएगी, मुख्यमंत्री ने कैबिनेट में प्रस्तुत करने को कहा

मध्य प्रदेश में सहकारिता नीति 31 अगस्त तक लागू की जाएगी

भोपाल। जागत गांव हमार

मध्य प्रदेश में सहकारिता के माध्यम से रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। इसके लिए सरकार सहकारिता नीति लागू करेगी। इसमें स्वास्थ्य सेवा, खाद्य प्रसंस्करण, खनिज, इवेंट मैनेजमेंट, पशु आहार, सेवा, ग्रामीण परिवहन आदि क्षेत्रों में प्राथमिक समिति से लेकर महासंघ गठित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सहकारिता नीति के प्रविधानों का प्रस्तुतिकरण देखने के बाद इसे कैबिनेट में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

साथ ही कहा कि 31 अगस्त तक नीति लागू करने के लिए अधिनियम में जो भी संशोधन करने हो, वो समयसीमा में पूरे कर लिए जाएं। नए क्षेत्रों को चिन्हित कर विभिन्न विभागों से सुझाव भी लिए जाएं। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री नीति का प्रारूप केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह को देकर उन्हें भोपाल में प्रस्तावित सहकारिता सम्मेलन में आने

का आमंत्रण दे चुके हैं। सहकारिता विभाग ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित बैठक में प्रस्तावित सहकारिता नीति का प्रस्तुतीकरण किया। इस दौरान बताया कि सहकारिता के माध्यम से रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए नए क्षेत्रों में समितियां गठित की जाएंगी। इसके लिए कुछ क्षेत्र चिन्हित भी कर लिए गए हैं। त्रिस्तरीय व्यवस्था रहेगी। प्राथमिक समिति से जुड़ने वाले सदस्यों में लाभांश का वितरण होगा। समिति को मार्गदर्शन देने और निगरानी करने का काम जिला स्तरीय समिति करेगी। प्रदेश स्तर पर महासंघ होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उचित मूल्य दुकानों को बहुउद्देशीय उपभोक्ता सेवा केंद्र के रूप में संचालन करने की योजना को शीघ्रता से लागू करें। इससे सहकारी समितियों की आय बढ़ेगी। सहकारिता नीति के क्रियान्वयन के लिए अधिनियम में आवश्यक संशोधन 31 अगस्त तक कर लिए जाएं। जिला स्तरीय कोर ग्रुप का गठन एक माह के भीतर करें। बैठक में सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव केसी गुप्ता सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

सहकारी समितियों के आडिट की पारदर्शी रहे व्यवस्था

मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारी संस्थाओं के आडिट की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होना चाहिए। इसके लिए आडिटर का आवंटन आनलाइन साफ्टवेयर के माध्यम से हो। जिला सहकारी बैंकों में एटीएम और मिनी एटीएम की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तेजी से काम किया जाए। गृह निर्माण सहकारी समितियों की पूरी जानकारी पोर्टल पर होनी चाहिए ताकि कोई भी उसे देख सके। सहकारी समितियों के गठन के लिए आवश्यक नियम बनाकर पोर्टल पर उपलब्ध कराए जाएं। जो सेवाएं आनलाइन नहीं हैं उन्हें आनलाइन किया जाए। लोक सेवा गारंटी अधिनियम में भी सेवाओं को जोड़ा जाए। निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी लाएं ताकि जल्द परिणाम आ सकें।

सफल प्रयासः नौरादेही वन्यप्राणी अभ्यारण्य में बढ़ता बाघों का कुनबा

मप्र के सागर जिले में स्थित लगभग 1200 वर्ग किमी. में फैला नौरादेही वन्यप्राणी अभ्यारण्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यप्राणी अभ्यारण्य है। इसकी सीमा सागर, दमोह और नरसिंहपुर जिलों पर है। नौरादेही मध्यप्रदेश का एक महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र है, यह भारत कि दो प्रमुख नदी गंगा और नर्मदा बेसिन के मध्य स्थित है, जिसके कारण यहां की जैवविविधता का एक अपना अलग ही महत्व है। नौरादेही के वन मुख्यतः विंध्य प्रकार के हैं। यहां विशेषकर शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं जिनमे कई हिस्सों में सागौन प्रमुख है एवं कुछ स्थानों को छोड़कर ज्यादातर भाग में मिश्रित खुले पर्णपाती वन पाए जाते हैं। कोपरा, बामनेर और बेयरमा यहां की मुख्य नदियां हैं जो अभ्यारण्य को वर्ष भर सिंचित रखती हैं। नौरादेही कई तरह के प्रवासी पक्षियों, गिद्धों, मगरमच्छ एवं भेड़ियों का प्रमुख आवास है, प्रदेश में पाए जाने वाले गिद्धों की सातों प्रजातियां देखी जा सकती हैं।

नौरादेही वन्य प्राणी अभ्यारण्य का इतिहास काफी पुराना है और नौरादेही के वन यहां हुए राजाओं एवं शासकों की पसंदीदा शिकारगाह रहे हैं, जहां पर राजा महाराजा बाघों एवं अन्य वन्य प्रणियों का शिकार किया करते थे। गोंड शासिका रानी दुर्गावती की भी यह पसंदीदा शिकारगाह थी। इतिहास में बाघों की उपस्थिति के कई प्रमाण होने के बाद भी नौरादेही बाघों को लेकर कभी भी चर्चा का विषय नहीं रहा, शायद इसलिए की यहां बाघ दिखाई नहीं देते थे, या शायद यहां से बाघ विलुप्त हो चुके थे।

पर फिर भी कभी-कभी भूले भटके पास में स्थित पन्ना के जंगलों से बाघों का आना-जाना यहां हमेशा से ही बना रहा है। वर्ष 2010 में यहां पन्ना टाइगर रिजर्व से एक बाघ यहां आ गया था, जो उसके बाद से अगले कुछ सालों तक लगातार आता-जाता रहा, परन्तु कोई साथी न मिल पाने या किसी और अन्य कारण से वो यहां स्थाई रूप से रुक नहीं पाया। बाघों के लिए अनुकूल आवास होने के बाद भी यहां बाघों का न होना वन विभाग को हमेशा से ही खटकता रहा, और बाघों को यहां दोबारा बसाना एक चुनौती भरा कार्य था। अभ्यारण्य के अंदर कई गांव मौजूद थे, जिसके कारण यहां जैविक दबाब भी बहुत ज्यादा था। साथ ही शाकाहारी वन्यप्राणियों की संख्या भी संतोषजनक नहीं थी, शायद एक ये भी कारण था कि बाघ जो पन्ना या अन्य संरक्षित क्षेत्रों से इलाकों की तलाश में यहां पहुंच रहे थे, वो स्थाई नहीं हो पा रहे थे।

परन्तु मप्र वन विभाग ने इस चुनौती को स्वीकार किया और बाघों को दोबारा नौरादेही में बसाने की कवायद शुरू की। इसी के अंतर्गत वर्ष 2018, कान्हा टाइगर रिजर्व से एक बाघिन नौरादेही लायी गयी, ये बाघिन कोई और नहीं बल्कि पेंच टाइगर रिजर्व की मशहूर बाघी-नाला बाघिन के शावकों में से एक थी। जिनको उनकी मां की मृत्यु हो जाने के बाद कान्हा में रखा गया था।

इस बाघिन को नाम दिया गया एन 1 (राधा), एन 1 नौरादेही में बाघ पुर्नस्थापना की बुनियाद थी और इस बुनियाद को मजबूत बनाने के लिए बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से एक नर बाघ एन 2 को लाया गया। एन 1 एवं एन 2 दोनों ही नौरादेही बाघ पुर्नस्थापना के मील का पत्थर साबित होने वाले थे।

नौरादेही वन प्रबंधन के द्वारा बाघ पुर्नस्थापना को सफल बनाने के लिए कई प्रयास किये गए, दोनों नए बाघों को कुछ दिन मनुष्य हस्तक्षेप से दूर पानी एवं उचित आवास सुविधा युक्त विशाल बाड़े में रखा गया एवं उसके बाद इन्हें जंगल में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया गया।

अभ्यारण्य के अंदर कई गांव स्थित थे, बाघों के आने से इन गांव में रहने वाले लोगों एवं बाघों के बीच संघर्ष बढ़ने की आशंका थी जो इस योजना को विफल कर सकती थी। परन्तु इन गांव में रहने वाले लोगों का रवैया बाघों एवं अन्य वन्यप्राणियो के प्रति हमेशा से ही सकारात्मक रहा है और इन्होने बाघों को सहर्ष स्वीकार किया।

वन प्रबंधन द्वारा किए प्रयासों का परिणाम मिलने में भी ज्यादा देर नहीं लगी, और मई 2019, बाघिन एन 1 तीन नन्हें बाघ शावकों के साथ इनकी निगरानी के लिए लगाए गए कैमरा ट्रैप में नजर आयी और नौरादेही में बाघों की संख्या 2 से बढ़कर 5 हो गयी। इन नन्हें बाघ शावकों को एन 111, एन 112 एवं एन 113 नाम दिया गया, जो कि

संदीप चौकस
वरिष्ठ परियोजना अधिकारी,
डब्ल्यूडब्ल्यूएफ, इंडिया

सेवाराम मलिक
उप-वनमंडल अधिकारी, मप्र.
(राज्य वन सेवा)

बाघों को नामकरण करने की एक सामान्य प्रक्रिया है।

नौरादेही का प्रबंधन इन पांच बाघों की निगरानी और देखरेख की योजना बना ही रहा था, कि जनवरी 2021 में कैमरा ट्रैप की फोटो को चेक करते समय अभ्यारण्य के स्टाफ को एक नया मेहमान बाघ (एन3) नजर आया,जो यहां मौजूद बाघों से बिलकुल अलग था, आसपास के संरक्षित क्षेत्रों में कैमरा ट्रैप की फोटो मिलान करने पर भी ये मालूम न चल सका कि ये नया बाघ कहां से आया है? ऐसा माना गया कि शायद ये बाघ पन्ना टाइगर रिजर्व से यहां आया है, या शायद ये यहां पहले से ही था और निगरानी बढ़ने पर अब नजर आने लगा। कुछ भी हो, नौरादेही को उसका छठवां बाघ मिल गया था। नवंबर 2021, बाघिन एन 1 दूसरी बार दो नन्हें शावकों के साथ नजर आयी। हाथी दल के द्वारा निगरानी करने पर ज्ञात हुआ की उसने दो नए शावकों को जन्म दिया है। ये नौरादेही प्रबंधन जिसने बाघों के संरक्षण में एवं पुर्नस्थापना में दिन रात एक कर दिए थे के लिए एक अविस्वरणीय समय था।

अप्रैल 2022, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ-इंडिया की टीम नौरादेही वन्यप्राणी अभ्यारण्य में अखिल भारतीय बाघ आंकलन-2022 के कार्य में वन विभाग का सहयोग कर रही थी। तभी खबर आयी कि हाथी गस्ती दल, जो की रेडियो कॉलर बाघिन एन 112 की निगरानी कर रहा था, उसने बाघिन के साथ दो नन्हें शावकों को देखा है।

नौरादेही के वन परिक्षेत्र अधिकारी वर्मा जी से संपर्क करने पर ये बात एकदम पुख्ता हो गयी। सारा नौरादेही का वन अमला इस बात से काफी खुश था क्यूंकि नौरादेही में बाघों की संख्या में दो नए बाघों का और इजाफा हो गया था, ये दो नए शावक नौरादेही में किये गए बाघ पुर्नस्थापना परियोजना की सफलता को बयान कर रहे थे, जो की नौरादेही प्रबंधन के अथक प्रयासों का ही नतीजा है।

अभी हाल ही में ये पता चला है कि बाघिन एन 1 ने दूसरी बार दो नहीं, बल्कि चार शावकों को जन्म दिया था। और अब नौरादेही में बाघों की संख्या 6 से बढ़कर 12 हो गयी है (एन 1 के पिछले तीन शावक (एन 111, एन 112, एन 113) एवं अभी वर्तमान में चार शावक, एन 2 एवं एन 3 और एन 112 के दो शावक)।

बाघों की बढ़ती संख्या हर्ष का विषय तो है, परन्तु इसे बनाये रखने के लिए और भी पड़ाव पार करने हैं। इनमे सबसे ज्यादा कठिन है जैविक दबाब को रोकना, नौरादेही के अंदर 72 गांव थे, जिनमे से 22 गावों को स्वैच्छिक विस्थापन प्रक्रिया के तहत विस्थापित किया जा चुका है परन्तु 50 गांव अभी भी अभ्यारण्य के अंदर ही हैं।

इन गांव के निवासी पूरी तरह अभ्यारण्य के जंगल पर ही निर्भर हैं, गांव के पालतू पशुओं की चराई भी एक महत्वपूर्ण विषय है। जंगल पर इन गांव की निर्भरता से जैविक दबाब बढ़ता जा रहा है।

अभ्यारण्य में अन्य शाकाहारी जानवरों की संख्या कम होने के कारण बाघों द्वारा पालतु मवेशियों का शिकार कर लिया जाता है जिसके कारण मानव-बाघ संघर्ष बढ़ने की सम्भावना एवं गांव वालों में असंतोष की भावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। जिसके लिए अंदर स्थित गावों से सामंजस्य बनाये रखना जरुरी है।

वनों की आग भी एक चुनौतीपूर्ण विषय है, हर वर्ष गर्मी के मौसम में आग से जंगल को काफी नुक्सान होता है आग से जंगल में प्राकृतिक वनस्पतियों की जगह खरपतवार प्रजातियां ले सकती हैं जिससे जंगल का पर्यावास शाकाहारी वन्यप्राणियो के अनुकूल नहीं रहता।

जल प्रबंधन के लिए तालाबों एवं सौसर का निर्माण, गश्ती दलों एवं गश्ती वाहनों की संख्या को भी सुचारु किया जाना आवश्यक है। नौरादेही में वनों की सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण विषय है जिसके लिए वनरक्षकों एवं वन श्रमिकों द्वारा लगातार गश्ती कर निगरानी रखी जाती है परन्तु गश्ती वाहनों की संख्या को बढ़ानेआवश्यकता है जिससे बाघों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

चार साल में ही दो का छह, छह का बारह; नौरादेही में बाघों की यह बढ़ती संख्या बाघ पुर्नस्थापना परियोजना कि सफलता की कहानी कह रहे हैं, और इस बात का प्रतीक है कि नौरादेही अभ्यारण्य बाघों के लिए एक उपयुक्त एवं अनुकूल आवास है।

बाघ प्रदेश बनने में राष्ट्रीय उद्यानों के प्रबंधन की मुख्य भूमिका

सभी वन्य जीवों में बाघ को विशाल हृदय वाला संभ्रांत प्राणी माना जाता है। यह गर्व की बात है कि मप्र को बाघ प्रदेश का दर्जा मिला है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मप्र के लिये विशेष महत्व का दिन है। यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाघों की जातियों की घटती संख्या, उनके अस्तित्व और संरक्षण संबंधी चुनौतियों के प्रति जन-जागृति के लिए मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाए जाने का निर्णय वर्ष 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग बाघ सम्मेलन में किया गया था। जिसमें बाघ की आबादी वाले 13 देशों ने वादा किया था कि वर्ष 2022 तक वे बाघों की आबादी दोगुनी कर देंगे।

बाघों की संख्या में 33 प्रतिशत की वृद्धि चक्रों के बीच अब तक सबसे अधिक दर्ज की गई है, जो वर्ष 2006 से 2010 तक 21 प्रतिशत और वर्ष 2010 से 2014 तक 30 प्रतिशत थी। बाघों की संख्या में वृद्धि, वर्ष 2006 के बाद से बाघों की औसत वार्षिक वृद्धि दर के अनुरूप थी। मध्यप्रदेश में देश में सबसे अधिक संख्या में 526 बाघ हैं। इसके बाद कर्नाटक में 524 बाघ और उत्तराखंड 442 बाघ के साथ तीसरे नंबर पर हैं। यह देश और विशेष रूप से मध्यप्रदेश के लिए गर्व का विषय है। वर्ष 2022 की समय-सीमा से काफी पहले सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से यह उपलब्धि हासिल कर ली गयी है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहल के परिणामस्वरूप बाघों की संख्या में वृद्धि के लिये निरंतर प्रयास हो रहे हैं। बाघ रहवास वाले क्षेत्रों के सक्रिय प्रबंधन के फलस्वरूप बाघों की संख्या में भी लगातार वृद्धि हो रही है। विश्व वन्य-प्राणी निधि एवं ग्लोबल टाईगर फोरम द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार विश्व में आधे से ज्यादा बाघ भारत में हैं। मध्य भारत भू-दृश्य भारत में बाघों के अस्तित्व के लिये अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मध्यप्रदेश के कॉरिडोर से ही उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत के बाघ रिजर्व आपस में जुड़े हुए हैं।

प्रदेश में बाघों की संख्या बढ़ाने में राष्ट्रीय उद्यानों के बेहतर प्रबंधन की मुख्य भूमिका है। राज्य शासन की सहायता से 50 से अधिक गांवों का विस्थापन कर बड़ा भू-भाग जैविक दबाव से मुक्त कराया गया। फलस्वरूप वन्य-प्राणियों के रहवास क्षेत्र का विस्तार हुआ है।

कान्हा, पेंच और कूनो पालपुर के कोर क्षेत्र से सभी गाँव को विस्थापित किया जा चुका है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का 90 प्रतिशत से अधिक कोर क्षेत्र भी जैविक दबाव से मुक्त हो चुका है। विस्थापन के बाद घास विशेषज्ञों की मदद लेकर स्थानीय प्रजातियों के घास के मैदान विकसित किये जा रहे हैं, जिससे शाकाहारी वन्य-प्राणियों के लिये वर्ष भर चारा उपलब्ध होता रहे।

सभी संरक्षित क्षेत्रों में रहवास विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। विगत एक वर्ष में 500 से अधिक चीतलों को अधिक संख्या वाले हिस्से से कम संख्या वाले एवं चीतल विहीन क्षेत्रों में सफलता से स्थानांतरित किया गया है। इससे चीतल, जो कि बाघों का मुख्य भोजन है, उनकी संख्या में वृद्धि होगी और पूरे भू-भाग में चीतल फैल जायेंगे।

राष्ट्रीय उद्यानों के प्रबंधन में मध्यप्रदेश शीर्ष पर: मध्यप्रदेश ने टाइगर राज्य का दर्जा हासिल करने के साथ ही राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों के प्रभावी प्रबंधन में भी देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को यूनेस्को की विश्व धरोहर की संभावित सूची में शामिल किया गया है। भारत सरकार द्वारा जारी टाइगर रिज़र्व के प्रबंधन की प्रभावशीलता मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार पेंच टाइगर रिजर्व ने देश में सर्वोच्च रैंक हासिल की है। बांधवगढ़, कान्हा, संजय और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन वाले टाइगर रिजर्व माना गया है। इन राष्ट्रीय उद्यानों में अनुपम प्रबंधन योजनाओं और नवाचारी तरीकों को अपनाया गया।

वन्य-जीव संरक्षण मामलों पर नीतिगत निर्णय लेने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा प्रभावी प्रबंधन के आकलन से संबंधित आँकड़ों की आवश्यकता होती है। ये आंकड़े संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के विश्व संरक्षण निगरानी केंद्र में रखे जाते हैं।

टाइगर रिजर्व की प्रबंधन शक्तियों का आकलन कई मापदण्डों पर होता है- योजना, निगरानी, सतर्कता, निगरानी स्टाफिंग पैटर्न, उनका प्रशिक्षण, मानव-वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन, सामुदायिक भागीदारी, संरक्षण, सुरक्षा और अवैध शिकार निरोधी उपाय आदि।

पेंच टाइगर रिजर्व के प्रबंधन को देश में उत्कृष्ट माना गया है। फ्रंटलाइन स्टाफ को उत्कृष्ट और ऊर्जावान पाया गया है। वन्य-जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में दर्ज सभी मामलों में पैरवी कर आरोपियों को दंडित करने में प्रभावी काम किया गया है।

इंदौर में जन्मा दुनिया का पहला तीन रंग का बाघ

इंदौर के चिड़ियाघर में सफेद बाघिन रागिनी ने तीन शावकों को जन्म दिया। तीनों अलग-अलग रंग के हैं। इनमें से एक शावक तीन रंग (सफेद, पीला और काला) का है। चिड़ियाघर प्रबंधन का दावा है कि ऐसे रंग संयोजन का बाघ दुनिया में कहीं भी नहीं है। सफेद बाघिन रागिनी को काले बाघ विक्की के साथ बाड़े में रखा गया था। रागिनी नौ साल जबकि विक्की छह साल का है। दोनों को ओड़िशा के नंदनकानन से लाया गया था। रविवार को दोपहर को जब दर्शक बाघिन को देख रहे थे, तभी उसने तीनों शावकों को जन्म दिया। अपनी आंखों के सामने बाघिन के बच्चों का जन्म होते देखना यहां मौजूद दर्शकों के लिए भी अनूठी घटना थी। एक शावक तीन रंगों का है। इसके शरीर पर सफेद, पीला और काला रंग है। तीन रंगों वाला बाघ दुनिया में और कहीं भी नहीं है। इसके अलावा एक शावक ऊपर से पूरा काला और नीचे से सफेद है जबकि तीसरा काला ज्यादा है और कुछ हिस्सा पीला है। शावकों के थोड़ा बड़ा होने पर रंग संयोजन ज्यादा स्पष्ट होगा।

चिड़ियाघर प्रभारी डा. उत्तम यादव के अनुसार बाघिन और शावक स्वस्थ हैं। बाघिन बच्चों को दूध भी पिला रही है। हम लगातार बाघिन और शावकों का ध्यान रख रहे हैं। यह इंदौर के लिए बड़ी उपलब्धि है कि यहां तीन रंगों वाले शावक का जन्म हुआ है। इसके पहले कहीं भी ऐसे शावक का जन्म नहीं हुआ है। यह भी पहली बार है जब सफेद बाघिन और काले मलेनिस्टिग बाघ की मैटिंग हुई है।

कोदो-कुटकी की खेती करने में रुचि नहीं दिखा रहे किसान

विलुप्त होने की कगार पर वनांचल की प्रमुख फसल

प्रदीप शर्मा, हरदा। जागत गांव हमार

जिले की पारंपरिक फसलें लुप्त होने की कगार पर है। नई पीढ़ी के बच्चों को तो संभवत: नाम तक नहीं मालूम है और ना ही अनाज को देखे हैं। 80-90 के दशक में कोदा-कुटकी ज्यादा हेक्टेयर में बोई जाती थी। गेहूं की फसल आते ही कोदो, कुटकी, समां कलधना (लाल चांवल), ज्वार, मक्का आदि फसलों को बोना किसानों ने बंद कर दिया है। मक्का तो बोई जा रही है, ज्वार, कोदो, कुटकी आदि तो बंद होने की कगार पर है।

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पहले बोई जाने वाली फसल लाभदायक पौष्टिक शुगर फ्री होती थी। जब से पुरानी फसलें नहीं बोई जा रही है तब से डायबिटीज के मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। अनाज नहीं मिल पाने के कारण भोजन के रूप में उसका सेवन नहीं हो पा रहा है। गेहूं-चांवल को खाद, दवाओं बीज के दम पर पैदा की जा रही है। जिसका स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ रहा है।

कोदो-कुटकी असल शुगर फ्री है। डायबिटीज के मरीजों के लिये यह अनाज रामबाण सिद्ध हो सकती है। इससे शरीर में शुगर का स्तर बढ़ने से रोका जा सकता है और ज्यादा परहेज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कुपोषण में भी लाभ होगा। स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होने के कारण कोदो, कुटकी, समां कलधना (लाल चांवल) और ज्वार जैसी फसलों को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है। किसानों को प्रोत्साहन देकर फसल को लुप्त होने से बचाया जा सकता है।

प्रोत्साहन की जरूरत

लुप्त होने से पारंपरिक फसलों को बचाने के लिए प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्यकता है। कोदो, कुटकी, समां कलधना (लाल चांवल), ज्वार, मक्का, ज्वार, जो, बर्रा आदि फसलों के महत्व को समझते हुए लुप्त होने से बचाने की दिशा में पहल की जाए। किसानों को जागरूक किया जाए और फसल अनाज तैयार होने पर बाजार उपलब्ध कराया जाए। अच्छा रेट मिलेगा तो निश्चित से किसान फसल बोने में रुचि दिखाएंगे, इससे फसलें लुप्त होने से बच जाएगी और लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिल सकेगा।

सरकार द्वारा प्रोत्साहन देने में कोताही

लुप्त होने की कगार पर पहुंची ज्वार, बाजरा, कोदा-कुटकी, समां कलधना (लाल चांवल) आदि फसलों को बढ़ावा देने में सरकार द्वारा कोताही बरती जा रही है। किसानों को बीज और प्रोत्साहन के लिए और कोई ठोस प्रयास नहीं किए जा रहे हैं, जिसके कारण किसान फसल बोने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। जहां एक और कोदो-कुटकी बोने और अनाज तैयार करने में मेहनत अधिक लगती है और मजदूरी अधिक लगने के कारण पर्याप्त रेट नहीं मिल पाता है। जिसके कारण आदिवासी किसानों का मोहभंग हो गया है। पहले बोरी, राजाबारी, कैली, कचनार सहित वनांचल के अनेक ग्रामों में काफी संख्या में आदिवासी फसल बोते थे। कटाई और थ्रेसिंग की सुविधा का अभाव होने के कारण और दिक्कत सामने आती थी। इन्हीं सब परेशानियों से त्रस्त होकर किसानों ने पारंपरिक फसलों की खेती करना करीब-करीब बंद कर दिया है।

किसानों को दिया जाए अनुदान

लुप्त प्राय फसलों की खेती करने वाले किसानों को अनुदान देने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। अनुदान पाने के लालच में किसान खेती करेंगे। इससे फसल लुप्त होने से बच जाएगी और शुगर फ्री होने के कारण डायबिटीज के मरीज उसका सेवन कर स्वास्थ्य को अच्छा बना सकते हैं। प्राचीन फसल से एक अलग पहचान बनेगी। शोध करके लुप्त प्राय: फसलों की ओर अच्छाइयों और गुणों का पता लगाया जाए और इस को ध्यान में रखते हुए फसल को लुप्त होने से बचाने का प्रयास किया जाए। कोदो-कुटकी की खेती करने में रुचि नहीं दिखा रहे किसान वनांचल की प्रमुख फसल लुप्त होने की कगार पर कृषि मंत्री का क्षेत्र हरदा जिला प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल हरदा जिले के हैं, ऐसी लुप्त प्राय- फसलों को बचाने के लिए सरकार द्वारा पहल की जानी चाहिए। नियम, कानून, प्रोत्साहन, अनुदान आदि की व्यवस्था कर किसानों को राहत पहुंचाई जाए। श्री पटेल इस दिशा में पहल करेंगे तो निश्चित रूप से फसल को लुप्त होने से बचा जा सकता है और डायबिटीज वालों को एक अच्छा आहार मिल सकता है।

गौमूत्र से कीटनाशक दवा बनाने की विधि

अन्नदाता इस तरह बनाएं गौमूत्र से कीटनाशक दवा

भोपाल। जागत गांव हमार

देश में किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा जैविक एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। जैविक खेती से जहां फसल उत्पादन की लागत में कमी आती है वहीं गुणवत्ता युक्त उपज भी प्राप्त होती है। किसान अपने घरों पर ही आसानी से जैविक खाद एवं कीटनाशक बना सकते हैं जिससे इनमें लगने वाली लागत को कम किया जा सकता है। गौ-मूत्र से बना कीटनाशक बाजार में मिलने वाले रासायनिक पेस्टीसाइड का बेहतर और सस्ता विकल्प है। इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, रासायनिक कीटनाशक से कई गुना अधिक होती है। खेतों में इसके छिड़काव से सभी प्रकार की कीटों पर नियंत्रण में मदद मिलती है। पत्ती खाने वाले, फल छेदन तथा तना छेदक जैसे अधिक हानि पहुंचाने वाले कीटों के प्रति इसका उपयोग अधिक लाभकारी है। गौमूत्र कीटनाशक, खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता और उसके स्वाद को बनाए रखने, खेती की उर्वरा शक्ति के साथ-साथ कृषि पर्यावरण एवं स्वास्थ्य के लिए बेहतर है।

किसान इस तरह बनाएं गौमूत्र से कीटनाशक

फसलों में विभिन्न प्रकार के कीटों को नियंत्रित करने के लिए किसान आसानी से घर पर ही कीटनाशक बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए 10 लीटर गौमूत्र में 2-3 किलो नीम की पत्ती के साथ सीताफल, पपीता, अमरूद एवं करंज की 2-2 किलो पत्तियां मिलाकर उबालना होता है। जब इसकी मात्रा 5 लीटर तक हो जाए तब इसे छान कर ठंडा कर बोतल में पैकिंग की जाती है। इस तरह 5 लीटर गौमूत्र कीटनाशक तैयार हो जाता है।

फसलों में इस तरह करें गौमूत्र से बनाए गए कीटनाशक का छिड़काव

दो से ढाई लीटर गौमूत्र कीटनाशक को 100 लीटर पानी में मिलाकर सुबह-शाम खड़ी फसल पर 10 से 15 दिनों के अंतराल में छिड़काव करने से फसलों का बीमारियों एवं तना छेदक कीटों से बचाव होता है। गौमूत्र कीटनाशक का उपयोग कीट का प्रकोप होने के पूर्व करने पर अधिक प्रभावशाली होता है। यह रोग नियंत्रक बायो डिग्रेबल है, जो वातावरण के लिए पूर्णत: सुरक्षित है। इसके उपयोग से कीटों में इसके प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि यह मल्टीपल एक्शन से कीट नियंत्रण करता है। गौमूत्र कीटनाशक से मित्र कीटों को हानि नहीं होती है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार गौमूत्र कीटनाशक बनाने पर प्रति लीटर 39 रुपए की लागत आती है, जिसमें इसके एक लीटर पैकेजिंग का खर्च 15 रुपए शामिल है। यदि केन में पैकेजिंग की जाए तो इसकी लागत और कम हो जाती है।

एवोकाडो फल स्वास्थ के लिए काफी लाभकारी

ब्रिटेन में पढ़कर भोपाल में एवोकाडो की खेती कर रहे हर्षित गोधा

भोपाल। जागत गांव हमार

एवोकाडो फल स्वास्थ के काफी लाभकारी होता है। इसे सबसे महंगे फलों में गिना जाता है। भारत में इसकी खेती बेहद कम पैमाने पर होती है। लेकिन भोपाल के रहने वाले हर्षित गोधा नाम के एक युवक ने एवोकाडो की खेती शुरू कर किसानों को एक नई राह दिखाई है। बता दें कि हर्षित गोधा साल 2013 में बीबीए की पढ़ाई करने के लिए यूके (ब्रिटेन) गए थे। वहां उन्हें अपनी फिटनेस के प्रति सजग रहने की आदत पड़ गई। वह हेल्दी डाइट लेने लगे, जिसमें एवोकाडो जरूर शामिल होता था। साल 2017 के दौरान एवोकाडो का सेवन करते समय उनकी नजर उसके रैपर पर पड़ी। उन्होंने पाया जिस फल को वह खा रहे हैं, उसे इजरायल में उगाया गया है। तब उनके दिमाग में ख्याल आया कि जब इसकी खेती इतने गर्म देश वाले जलवायु वाले देश में हो सकती है तो भारत में क्यों नहीं।

इजरायल में ली एवोकाडो की खेती की ट्रेनिंग- हर्षित बताते हैं कि दिमाग में इस आइडिया के आने के बाद ही वह एवोकाडो की खेती की ट्रेनिंग के लिए इजरायल के किसानों से संपर्क करने की कोशिश करने लगे। वहां के किसानों को वह लगातार ई-मेल भी करते रहे। उनमें से एक किसान उनको एवोकाडो की खेती की बारिकियों को सीखाने को तैयार हो गए। फिर वह टूरिस्ट वीजा पर इजरायल पहुंच गए। इस दौरान वहां तकरीबन एक एवोकाडो की खेती से जुड़ी छोटी से छोटी चीजें सीखते रहे हैं। फिर वापस यूके पहुंच कर और डिग्री पूरी और 2018 में वे वापस भारत लौट आएं।

ऐसे शुरू की खेती

वापस आने के बाद हर्षित ने एवोकाडो की खेती करने का पूरा मन बना लिया। वह आगे बताते हैं कि उन्होंने 2019 में इज़राइली सहयोगियों को भारत आने का न्योता भेजा। ये सभी सहयोगी उनके बुलावे पर पर भारत आए। इस दौरान इन इजरायलियों ने भोपाल में ज़मीन तैयार करने से लेकर इजराइली एवोकाडो के मदर प्लांट मुहैया कराने का काम किया। इस दौरान हमने पता करने की कोशिश की क्या भोपाल में इसकी खेती की भी जा सकती है। फिर हमने पांच एकड़ में पॉयलट प्रोजेक्ट के तौर पर एवोकाडो की खेती की शुरुआत। इसके लिए 1800 एवोकाडो के पौधे इजरायल से मंगाए गए। हालांकि आयात कानूनों की वजह से इसे मंगाने उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। हर्षित अब एवोकाडो फार्मिंग के बारे में सोशल मीडिया पर जागरुकता फैला रहे हैं। वह अन्य किसानों को भी इसकी खेती के लिए टिप्स देते रहते हैं। कई किसान उनसे संपर्क भी करते हैं। उनके मुताबिक देशभर के किसानों को भी इज़राइली एवोकाडो के पौधे बेच रहे हैं। उन्होंने इसके लिए इजराइल से करीब 4000 पौधे मंगवाए हैं। इन सारे पौधों की बुकिंग हो गई है।

कमा सकते हैं इतना मुनाफा

हर्षित के अनुसार भारत के किसानों के लिए काफी मुनाफे वाली फसल साबित हो सकती है। एक बार फसल लगाने के बाद इससे आप 40 से 50 साल तक मुनाफा कमाते रह सकते हैं। उन्होंने एक अनुमान के मुताबिक बताया कि इसकी खेती से आप सालाना 6 से 8 लाख रुपए तक का मुनाफा कमा सकते हैं। फसल के उत्पादन के हिसाब से ये मुनाफा आगे पीछे भी हो सकता है।

मुआवजे के लिए खाने पड़ते हैं धक्के, इसलिए किसान फसल बीमा कराने में नहीं दिखा रहे रुचि

फसल बीमा योजना से दूर भाग रहे किसान, हर साल घट रही संख्या

खेम राज मौर्य, शिवपुरी/श्योपुर। जागत गांव हमार

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम पर सरकार की ओर से भले ही किसानों के कल्याण के लिए बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत में इस योजना से जुड़ने वाले किसानों की संख्या हर साल घट रही है। फसल बीमा के तहत मुआवजा पाने को भी धक्के खाने पड़ते हैं। इससे किसानों में पीएम फसल योजना को लेकर रुझान घट रहा है। पांच साल पहले जहां जिलेभर में खरीफ और रबी सीजन के दौरान 41409 किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसलों का बीमा करवाया था। वहीं पांच साल बाद अब किसानों की संख्या घटकर 30247 रह गई है।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू किया था। इस स्कीम के तहत 9 फसलों को अधिसूचित किया है। इसके लिए किसानों से खरीफ सीजन में 2 प्रतिशत व रबी सीजन में 1.5 प्रतिशत प्रीमियम लिया जाता है। शुरुआत में फसल बीमा योजना अनिवार्य थी, लेकिन किसानों के लगातार विरोध के बावजूद इसे ऐच्छिक कर दिया। इसके बाद से किसानों का रुझान योजना के प्रति घट रहा है। अब किसानों को अगर इस योजना से नहीं जुड़ना है इसके लिए उन्हें संबंधित बैंक में लिखकर देना होता है। इसके बाद प्रीमियम नहीं काटा जाता।

खरीफ-रबि सीजन के दौरान फसल बीमा करवाने वाले किसान

वर्ष	बीमित किसान	लाभांवित किसान
2017-18	41409	9131
2018-19	38212	3633
2019-20	38791	2497
2020-21	36469	14526
2021-22	30247	प्रक्रियारत

अभी तक करीब 13 हजार किसानों ने कराया बीमा

वर्तमान खरीफ सीजन में जिले के करीब 13 हजार किसान ही अभी तक फसल बीमा करा पाए है। जबकि फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है और कृषि विभाग के अधिकारी फसल बीमा कराने को लेकर किसानों को जागरूक कर रहे है। लेकिन इसके बाद भी किसान फसल बीमा कराने को लेकर रुचि नहीं दिखा रहे है।

- फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित है। हम किसानों को फसल बीमा कराने के लिए जागरूक कर रहे है और बीमा के फायदे भी किसानों को बताए जा रहे है।

पी गुजरे
उप संचालक
कृषि, श्योपुर

- फसल बीमा योजना में मुआवजा निकालने का सिस्टम काफी जटिल है। इसके अलावा किसानों को पॉलिसी भी नहीं मिलती। इसलिए किसान फसल बीमा योजना से दूरी बना रहे है। शासन को इस दिशा में ध्यान देकर फसल बीमा योजना के नियमों में सरलता लानी चाहिए।

राधेश्याम मीणा,
प्रदेश अध्यक्ष,
भाकियू चढ़ूनी

मुआवजा सिस्टम भी नहीं ठीक

पीएम फसल बीमा योजना से पीछे हटने के कई कारण हैं। किसानों को धक्के खाने पड़ते हैं। आवेदन प्रक्रिया को सरल करने के दावे सरकार कर रही है, लेकिन इसके बावजूद बीमा पाने को किसानों को भटकना पड़ता है। किसान नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की कई कमियों के चलते किसान इससे दूर भाग रहे हैं। इस योजना की सबसे बड़ी कमी यह है कि इसमें पूरे गांव को इकाई माना जाता है। जब पूरे गांव के किसानों की फसल खराब होती है तो ही फसल को खराब माना जाता है। वहीं मुआवजा निकालने का सिस्टम भी ठीक नहीं है। इसके अलावा किसानों को पॉलिसी भी नहीं मिलती। ऐसे में किसानों के पास फसल बीमा का कानूनी रूप से कोई दस्तावेज भी नहीं होता। क्लेम में अगर कोई अड़चन पैदा हो जाए तो किसान की कोई सुनवाई नहीं है। कृषि विभाग के अधिकारी भी अपने हाथ खड़े कर देते हैं।

2021 में 14526 को मिला बीमा

वर्ष 2020-21 में खरीफ और रबी सीजन के दौरान जिले के 36469 किसानों ने फसल बीमा करवाया था। जिसके तहत बीमा कंपनी ने 14526 किसानों को उनकी फसल नुकसान का मुआवाजा 2176 लाख रूपए उनके खातो में डाला। जबकि वर्ष 2021-22 में दोनो सीजनों के दौरान जिले के 30247 किसानों ने फसल बीमा करवाया था। लेकिन अभी तक किसी भी किसानों को मुआवजा नहीं मिल सका है। संबंधित विभागीय अधिकारी मुआवजा मिलने के लिए प्रकिया चलने की बात कह रहे है। लेकिन मुआवजा कब मिलेगा,इसको लेकर स्पष्ट रूप से कुछ नहीं बता रहे है।

एनडीडीबी मृदा लिमिटेड डेयरी किसानों को घोल और गोबर की बिक्री से आय के रास्ते खोलेगी

नई दिल्ली। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने देश भर में खाद प्रबंधन की पहल को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एनडीडीबी एमआरआईडीए लिमिटेड का शुभारंभ किया।

इस अवसर पर केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉ. संजीव कुमार बाल्यान और डॉ. एल मुरुगन, अतुल चतुर्वेदी, सचिव, डीएएचडी, सरकार, भारत की। मीनेश शाह, अध्यक्ष, एनडीडीबी और एनडीडीबी मृदा, वर्षा जोशी, अतिरिक्त सचिव (सीडीडी), डीएएचडी, सरकार, भारत की, और संदीप भारती, एनडीडीबी एमआरआईडीए लिमिटेड के नवनियुक्त प्रबंध निदेशक उपस्थित रहे। केंद्र सरकार के अनुमोदन से, एनडीडीबी ने 9.50 करोड़ रुपए की चुकता पूंजी के साथ 1 जुलाई, 2022 को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एनडीडीबी एमआरआईडीए लिमिटेड, एक गैर-सूचीबद्ध पब्लिक लिमिटेड कंपनी की स्थापना की है।

इस अवसर पर, डॉ. बाल्यान ने एनडीडीबी एमआरआईडीए लिमिटेड पर एक ब्रोशर भी लॉन्च किया और डॉ. मुरुगन ने एनडीडीबी के सुधान ट्रेडमार्क को एनडीडीबी एमआरआईडीए लिमिटेड के अध्यक्ष और एमडी को सौंपा।

बायो गैस सेहोगी बचत

इस अवसर पर रूपाला ने कहा कि एनडीडीबी मृदा लिमिटेड डेयरी किसानों को घोल/गोबर की बिक्री से अतिरिक्त आय के रास्ते खोलेगी। खाना पकाने के ईंधन को बायोगैस से बदलने से किसानों को बचत होगी। गोजातीय गोबर के बेहतर उपयोग के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अधिकांश व्यक्तिगत पहल हैं। हालांकि, यह नई कंपनी प्रबंधन प्रयासों को खाद बनाने के लिए संरचित प्रोत्साहन प्रदान करेगी। इसके अलावा, गोबर आधारित खाद के उपयोग को बढ़ावा देने से धीरे-धीरे रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद की जगह ले ली जाएगी, जिससे आयात पर भारत की निर्भरता कम हो जाएगी। डॉ. बाल्यान ने कहा कि यह अपनी तरह की पहली कंपनी है, जो खाद प्रबंधन मूल्य श्रृंखला बनाकर गोबर के कुशल उपयोग पर ध्यान केंद्रित कर रही है जो डेयरी किसानों की आजीविका को बढ़ाने के साथ-साथ योगदान देने में भी योगदान देगी। स्वच्छ भारत मिशन और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना। खाद प्रबंधन पहल में भारत की वर्तमान एलपीजी खपत के 50 प्रतिशत के बराबर बायोगैस उत्पन्न करने और भारत की एनपीके आवश्यकता के 44 प्रतिशत के बराबर जैव-स्लरी का उत्पादन करने की क्षमता है। इसके अलावा, कुशल खाद प्रबंधन सामान्य भलाई और स्वच्छता को भी बढ़ावा देता है।

संभाग में 420 हेक्टेयर बचा सोयाबीन का रकबा

सोयाबीन की खेती से भंग होता विंध्य के किसानों का मोह, सिमट रहा रकबा

धनंजय तिवारी, रीवा। जागत गांव हमार

कभी नगदी फसल के रूप में जाने जानी वाली फसल सोयाबीन की खेती विंध्य में अब औपचारिकता बनकर रह गई है। पहले रीवा संभाग में लगभग दो लाख हेक्टेयर में इसकी बोने की जाती थी, किन्तु अब धीरे-धीरे सोयाबीन की खेती से किसानों का मोह भंग होता चला गया। आलम यह कि अब यह सिमटकर सिर्फ 10 हजार हेक्टेयर में रह गई है। स्थिति यह हो गई है कि अब किसानों के लिए सोयाबीन का बीज जुटाना भी मुश्किल हो जाता है। संभाग के सतना जिले में कुछ किसान सोयाबीन की खेती कर रहा है। जबकि शेष तीन जिले में 3-4 सौ हेक्टेयर में ही बोनी कर औपचारिकता की जा रही है।

किसानों के लिए बन रहा घाटे का सौदा- किसानों की मानें तो सोयाबीन की फसल अब घाटे का सौदा बनती जा रही है। उसका कारण यह है कि कभी पानी समय पर न मिलने की वजह से और कभी ज्यादा बारिश की वजह से सोयाबीन की फसल खराब हो जाती है। पिछले कुछ वर्षों में यदि देखा जाए तो बारिश की वजह से किसानों का काफी नुकसान हो चुका है, जिसकी भरपाई करना मुश्किल हो गया। दूसरी तरफ फसल होने के बाद बेचने की समस्या भी आती है।

सोया प्लांट का बंद होना भी बना कारण

जेपी ग्रुप द्वारा विंध्य में सोयाबीन फसल की अच्छे उत्पादन को देखते हुए सोया प्लांट की स्थापना की गई थी, लेकिन धीरे-धीरे फसल का रकबा कम होने के बाद ग्रुप ने अपना प्लांट बंद कर दिया, जिससे कुछ बचे-खुचे किसानों को भी इस खेती से मुंह मोड़ने को मजबूर कर दिया। अब आलम यह है कि रीवा जिले में सोयाबीन की खेती का रकबा घटकर 420 हेक्टेयर ही रह गया है, जो धीरे-धीरे समाप्त होता जा रहा है।

सतना में 9 हजार हेक्टेयर का लक्ष्य

जानकारों की मानें तो रीवा, सीधी एवं सिंगरौली में सोयाबीन की खेती अब पूरी तरह से दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। रीवा जिले में इस वर्ष महज 420 हेक्टेयर बोवनी का लक्ष्य रखा गया है। जबकि पिछले वर्ष 7 यह रकबा 1420 हेक्टेयर का था, लेकिन शुरू से ज्यादा बारिश हो जाने की वजह से पूरी फसलें खराब हो गई थी। इधर सतना जिले में इस वर्ष 9 हजार हेक्टेयर में सोयाबीन की बोवनी का लक्ष्य रखा गया है। पिछले वर्ष सतना में 2790 हेक्टेयर में सोयाबीन की बोवनी की गई थी। बताया गया है कि वहीं इस वर्ष सीधी सिंगरौली में भी थोड़े बहुत रकबे में सोयाबीन की बोनी का लक्ष्य रखा गया है। लगतार सोयाबीन की खेती का रकबा घटता जा रहा है। हालांकि लगतार होने वाली बारिश भी इसकी बोवनी में रुकावट पैदा करती है, किन्तु इस वर्ष बारिश कम है। इसके बाद भी रीवा जिले में सोयाबीन की खेती का रकबा सीमित रखा गया है।

» डोर-टू-डोर 800 घरों में पहुंचा रहे गुलाब
» आज साल में कमाते हैं 12 से 15 लाख

नर्मदापुरम में 20 साल पहले सुधीर ने की थी 15 पौधों से शुरुआत

देशी गुलाब से जिंदगी गुलजार

नर्मदापुरम। जागत गांव हमार

लीक से हटकर खेती करना लाभकारी हो सकता है, ये साबित किया है नर्मदापुरम जिले के किसान सुधीर वर्मा ने। जिला मुख्यालय से 40 किमी दूर सुधीर 8 एकड़ के खेत में देशी गुलाब की खेती कर रहे हैं। उन्होंने 20 साल पहले 10-15 गुलाब के पौधों से शुरुआत की थी। अब 8 एकड़ में पौधे लगाकर रोजाना 7 से 8 हजार रुपए के गुलाब रोज बेचते हैं। बड़े पैमाने पर की जा रही खेती से 10 से 11 स्थानीय लोगों को रोजगार भी दे रखा है। सुधीर के उपजाए देशी गुलाब की डिमांड इटारसी, नर्मदापुरम के अलावा हरदा के बाजारों में रहती है। सुधीर आठवीं तक ही पढ़े हैं, इसके बाद खेती करने लगे। सुधीर ने कहा कि ट्रेडिशनल खेती के साथ गुलाब की खेती उन्हें आर्थिक रूप से मजबूती देती है।

गुलाब के फूल की खेती में रोजाना की मेहनत जरूर है, लेकिन कमाई भी ट्रेडिशनल फार्मिंग से ज्यादा है। सुधीर रोज रात 3 बजे उठकर घर से 15 किमी दूर खेत पहुंचते है। इसके बाद मजदूरों के साथ गुलाब तोड़कर बाजार पहुंचाते हैं।

12 लोगों को मिला रोजगार

सुधीर की गुलाब की खेती से 12 स्थानीय लोगों को रोजगार से जोड़ा है। इससे उनके परिवार का जीवनयापन हो रहा है। नर्मदापुरम, इटारसी और हरदा में गुलाब के फूलों की थोक सप्लाई के अलावा 800 घरों में डोर-टू-डोर जाकर गुलाब के फूल की डिलेवरी करते हैं। पूजा के लिए लोग इन फूलों को मंगाते हैं। सुधीर बताते हैं कि थोक में जितनी कमाई नहीं, उससे ज्यादा फुटकर में होती है।

नौकरी से बेहतर कृषि

किसान सुधीर मानते हैं कि सर्विस से बेहतर व्यवसाय कृषि होता है। मेहनती व्यक्ति को खेती या बिजनेस करना चाहिए। नौकरीपेशा व्यक्ति की आय सीमित होती है। बिजनेस या कृषि में आय सीमित नहीं होती। सुधीर बताते हैं कि मौजूदा दौर में वह रोजाना 6 से 7 हजार रुपए कमाते हैं। अगर उनकी वार्षिक आय की बात की जाए तो 12 से 15 लाख रुपए है।

खेत तैयार करने की विधि

पौधरोपण के बाद उसकी सिंचाई करने के साथ ही उचित मात्रा में खाद की जरूरत होती है। इसके लिए ड्रिप से 19-19, क्लोरी-50, यूरिया, कैल्शियम, 0050, 13045 खाद देना पड़ता है। पौधरोपण के दो माह बाद से फूल आने लगते है। गुलाब के पौधे काफी नाजुक होते हैं। इसमें फफूंद जनित रोग, सफेद मकड़ी सहित कई रोग लग जाते हैं। ध्यान न दें, तो पूरा पौधा सूख सकता है। इस परेशानी से बचने के लिए पौधों को रोज देखना चाहिए। किसी भी पौधे में रोग के लक्षण दिखें, तो तुरंत उपचार करना चाहिए। इसके लिए 15 दिन में एक बार कीटनाशक का छिड़काव जरूर करना चाहिए।

फूल की कटिंग में सावधानी

गुलाब के फूलों की कटिंग में भी बड़ी सावधानी की जरूरत होती है। जमीन से डेढ़ फीट की हाइट तक ही कटिंग करना चाहिए। इसे नीचे से तीन से चार पत्ती छोड़कर तना सहित काटना पड़ता है। जितना लंबा तना होता है, उसकी कीमत उतनी ही अधिक मिलती है। तीन से चार पत्ती छोड़ने का मतलब ये है कि वहां से गुलाब के नए तने निकलते हैं। महीने में एक बार खरपतवार की निदाई करना चाहिए। जब फूल को चमकीले रंग की पंखुड़ियां मिल जाती हैं, तब इनकी कटाई की जाती है। पहले वर्ष में गुलाब के पौधे तैयार होते हैं, इसलिए पहले वर्ष में अधिक उत्पादन नहीं हो पाता है। वहीं दूसरे वर्ष में आपको इस गुलाब के फूलों से अच्छी उपज मिलने लगेगी। गुलाब के पौधे में मार्च में 45 से 50 दिनों की छंटाई के बाद फूल आने लगते हैं। आमतौर पर गुलाब के फूल पौधे पर 40 दिन तक रह सकते हैं।

ऐसी जलवायु चाहिए गुलाब के पौधे रोपने से पहले खेत में बेड की तरह जमीन तैयार करना होता है। 90 सेमी चौड़े और एक से डेढ़ फुट ऊंचे मिट्टी के बेड के बीच की दूरी 30 से 40 सेमी रखी जाती है। बेड बनाते समय गोबर का खाद या ऑर्गेनिक खाद डाला गया। बेड बन जाने के बाद हाथ से एक-एक कर पौधे रोपे जाते हैं। एक पौधे से दूसरे की दूरी 15 सेमी रखी जाती है। गुलाब के लिए 26-30 डिग्री तक का तापमान और जमीन में 70-85 प्रतिशत नमी की जरूरत होती है। इसे संतुलित रखना बड़ी चुनौती होती है। सबसे बड़ी चुनौती तापमान को संतुलित करने की होती है, एक बार तोड़ने के 30 से 40 दिन बाद फिर फूल खिल जाते हैं। यह क्रम पूरे साल चलता रहता है।

पौधारोपण के साथ पौधों की देखभाल का भी रखें ख्याल

भोपाल। बरसात का सीजन भला किसे पसंद नहीं होता। लोग इस मौसम में पौधारोपण भी खूब करते हैं। बस इस मौसम की परेशानी यह है कि बगीचे के कई पौधे ज्यादा पानी मिलने के कारण सड़ने लगते हैं। सड़क के किनारे और गार्डन में बहुत सारी हरी घास और खरपतवार उग जाते हैं। मानसून के सीजन में कई लोगों के घरों में पौधों में कीड़े भी लग जाते हैं। गुड़हल के पौधे में लगे सफेद कीड़े, गुलाब के पौधे में लगे काले कीड़े आदि इस सीजन में बहुत ज्यादा परेशान कर सकते हैं। अगर आपकी भी यही समस्या है और मानसून में ज्यादा पौधे सड़ रहे हैं तो हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे उपाय, जिन्हें अपनाने से इस सीजन में आपके पेड़ फूलों से भर जाएंगे।

पौधे में अलग से पानी ना डालें

सबसे पहला सुझाव यही है कि आप अलग से पानी इसके ऊपर ना डालें। फूल देने वाले पौधों को जितने पानी की जरूरत होती है, वो अधिकतर मानसून की वर्षा से पूरी हो जाती है। अगर आप रोजाना ही अपने पौधों को पानी देती हैं तो ऐसा ना करें। ये सीजन ऐसा नहीं है जिसमें रोजाना पानी दिया जाना चाहिए। ऊपरी मिट्टी सूखी दिखे तो पहले उसे थोड़ा खोदकर देखें। अगर उसमें नमी महसूस हो रही है तो ऊपर से पानी ना दें। दरअसल, इस सीजन में पौधों के खराब होने का सबसे अहम कारण ही यही होता है कि उनकी जड़ें ज्यादा पानी से सड़ जाती हैं।

माइस्ट स्प्रे का प्रयोग न करें

कई लोग पौधों को माइस्ट स्प्रे से पानी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोजाना इसकी जरूरत नहीं होती है और मानसून में तो इसकी जरूरत बिल्कुल ही नहीं होती है। ये पौधों को जरूरत से ज्यादा नम कर देगा और कीड़े बहुत ज्यादा आएंगे। गुड़हल का पौधा और गुलाब का पौधा इस माइस्ट स्प्रे के कारण सबसे ज्यादा सड़ता है और इसलिए आप पत्तियों में भी उस तरह से पानी ना डालें। हां, अगर दवा डाली जा रही है तो यकीनन मिस्ट स्प्रे की जरूरत पड़ेगी।

मानसून के कीड़ों को ऐसे रोकें

इस सीजन में गुड़हल और गुलाब जैसे पौधों में बहुत ज्यादा कीड़े होने लगते हैं। सफेद कीड़े पूरी तरह से फूलों और पत्तियों को खराब कर देते हैं। काले कीड़ों के साथ भी ऐसा ही होता है जो गुलाब के फूल में अधिकतर होते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो नीम तेल स्प्रे दें, इसे पौधों में डालने का भी एक तरीका है। आप 3-4 लीटर पानी में दो ढक्कन नीम ऑयल डालकर पौधों पर छिड़कें। इसे स्प्रे के फॉर्म में ही डालना है और ये जरूरी भी है।

फंगस से करें बचाव

मानसून के मौसम में इस समस्या से बहुत से लोग परेशान रहते हैं। ब्लैक फंगस कई सारे पौधों को मार देती है और साथ ही साथ पत्तियों का विकास भी रुक जाता है। ऐसे में होता ये है कि अगर किसी एक पौधे में ये हो रहा है तो पूरे बगीचे के कई पौधे इससे खराब हो जाते हैं। ऐसे में आप एपल साइडर विनेगर का इस्तेमाल करें। संक्रमित पौधे को इसी तरह से पानी देना है। एक लीटर पानी में दो बड़े चम्मच एपल साइडर विनेगर मिलाएं और उसके बाद उसे संक्रमित पौधे पर छिड़कें।

वैश्विक पर्यटन मानचित्र में शामिल होगी शिवपुरी की सांख्य सागर झील, मिला रामसर साइट का दर्जा

भोपाल। जागत गांव हमार

मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की सांख्य सागर झील को रामसर साइट का दर्जा मिला है। इसके पहले यह दर्जा भोपाल के भोज ताल (बड़ा तालाब) को मिल चुका है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस उपलब्धि के लिए प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि इसे वैश्विक पर्यटन मानचित्र में जगह मिलेगी। यह दर्जा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में जैव विविधता व पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों का पारितोषिक है।

सरकार व राज्य के प्रकृति प्रेमी नागरिकों द्वारा जैव विविधता व पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। झील संरक्षण के संबंध में ईरान के रामसर नगर में वर्ष 1971 में हुई एक अंतरराष्ट्रीय संधि के आधार पर अंतरराष्ट्रय महत्व की वेटलैंड साइट की सूची संधारित की जाती है। पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग ने बताया कि केंद्र सरकार ने प्रदेश के सांख्य सागर, सिरपुर तालाब व यशवंत सागर को रामसर साइट में शामिल

करने पर सहमति दी थी और स्विटजरलैंड के ग्रैंड शहर स्थित रामसर सचिवालय को प्रस्ताव भेजा था। जो अतिरिक्त जानकारी मांगी थी, वह भी केंद्र सरकार के माध्यम से उपलब्ध करा दी थी। अभी सांख्य सागर झील को रामसर साइट का दर्जा मिला है। अन्य प्रस्ताव को भी शीघ्र ही मंजूरी मिलेगी।

छात्रों ने कृषि विज्ञान केंद्र का किया भ्रमण, कृषि अनुसंधान एवं विस्तार की गतिविधियों पर चर्चा कर जानकारी प्राप्त की

खेमराज मौर्य, शिवपुरी। जागत गांव हमार

सरस्वती विद्यापीठ आवासीय विद्यालय फतेहपुर के 40 कृषि छात्रों द्वारा विद्यालय के अध्यापकों के साथ गतदिवस को कृषि विज्ञान केंद्र पर भ्रमण किया एवं केंद्र पर संचालित विभिन्न कृषि अनुसंधान एवं विस्तार की गतिविधियों पर चर्चा कर जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर छात्रों को स्वच्छता गतिविधि की शपथ दिलाई गई।

अंकुर अभियान के बारे में जागरूकता एवं वृक्षारोपण को प्रोत्साहन में सहभागिता के लिए बतलाया गया। साथ ही हर घर तिरंगा अभियान के बारे में भी जानकारी देते हुए केंद्र की विभिन्न प्रदर्शन इकाइयों का अवलोकन कराया तथा समन्वित कृषि प्रणाली इकाई के अंतर्गत वर्षा जल संरक्षण, रूफ वाटर हार्वेस्टिंग, अमरूद संतति इकाई, टमाटर बीज उत्पादन एवं प्रजनक बीज उत्पादन के बारे में भी केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा विस्तार से जानकारी दी। केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ.एम.के.भार्गव ने बताया कृषि

उद्यमिता एवं रोजगार के बारे में छात्रों को आत्मनिर्भर भारत के अभियान के बारे में भी जानकारी केंद्र के विभिन्न विशेषज्ञों एवं वैज्ञानिकों द्वारा बतलाई गई।

केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा-केंद्र सरकार चलाएगी अभियान

देश-विदेश में भी लोकप्रिय होगा बाजरा, किसानों का मिलेगा लाभ

भोपाल। जागत गांव हमार

बाजरा और अन्य पोषक अनाज को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार देश और विदेश में कई कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बना रही है। इसके अलावा, भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग, राज्य सरकारों के साथ, कृषि और किसान कल्याण विभाग और कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के समन्वय से पोषक अनाज को बढ़ावा देंगे। यह बात केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष विषय पर कृषि मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक के दौरान कही। दरअसल, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर, केंद्र सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के समक्ष साल 2023 को अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित करने का प्रस्ताव दिया था। केंद्र के प्रस्ताव को 72 देशों ने समर्थन दिया और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मार्च 2021 में साल 2023 को अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया।

उत्पादन-ब्रांडिंग पर फोकस- बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने आईवाईओएम-2023 के भव्य समारोह के लिए कार्यक्रमों की योजना बनाई है। आईवाईओएम-2023 की कार्ययोजना उत्पादन, खपत, निर्यात, ब्रांडिंग आदि को बढ़ाने की रणनीतियों पर केंद्रित है। सरकार ने बाजरा को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई योजना भी शुरू की है। प्रधानमंत्री की आत्मनिर्भर भारत अभियान घोषणा के हिस्से के रूप में, सरकार ने 31 मार्च 2021 को 10,900 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना नामक केंद्रीय योजना को मंजूरी दी। इस योजना को 2021-22 से सात साल की अवधि 2026-27 तक लागू किया जाएगा।

समिति का किया गया गठन

तोमर ने कहा कि योजना के प्राथमिक उद्देश्यों में वैश्विक खाद्य निर्माण चैंपियन बनाने और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में खाद्य उत्पाद के भारतीय ब्रांडों का सहयोग करना शामिल है। योजना के तहत सहायता प्रदान करने के लिए उच्च विकास क्षमता वाले विशिष्ट खाद्य उत्पादों की पहचान की गई है। इनमें बाजरे पर आधारित उत्पादों सहित पकाने के लिए तैयार/खाने के लिए तैयार खाद्य पदार्थ शामिल हैं। पोषक अनाज को लोकप्रिय बनाने के कार्यक्रमों और नीतियों की निगरानी के लिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की एक समिति और सचिव, डीए एंड एफडब्ल्यू और सचिव डीएआरई की अध्यक्षता में एक कोर समिति का गठन किया गया है।

सात सूत्र विकसित

सरकार ने आईवाईओएम के लिए सात सूत्र विकसित किए हैं जिन्हें संबंधित मंत्रालय द्वारा लागू किया जाएगा- उत्पादन/उत्पादकता में वृद्धि, पोषण और स्वास्थ्य लाभ, मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण और पकाने की विधि का विकास, उद्यमिता/स्टार्टअप/सामूहिक विकास, ब्रांडिंग लेबलिंग और प्रचार सहित जागरूकता पैदा करना, अंतरराष्ट्रीय पहुंच और मुख्यधारा के लिए नीतिगत कदम।

भारत बाजरे का प्रमुख उत्पादक

बाजरा प्रोटीन, फाइबर, खनिज, आयरन, कैल्शियम का एक समृद्ध स्रोत है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। भारत बाजरे का एक प्रमुख उत्पादक है, जो एशिया के उत्पादन का 80 प्रतिशत और वैश्विक उत्पादन का 20 प्रतिशत है। भारत में बाजरे की औसत उपज (1239 किलो/हेक्टेयर) भी वैश्विक औसत उपज 1229 किग्रा/हेक्टेयर से अधिक है।

वित्तपोषण के लिए मंजूरी

सरकार ने बाजरा को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। घरेलू और वैश्विक मांग पैदा करने और लोगों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए 2018 में राष्ट्रीय बाजरा वर्ष मनाया गया। बाजरे के पोषण मूल्य को देखते हुए सरकार ने अप्रैल 2018 में बाजरे को पोषक अनाज के रूप में अधिसूचित किया और बाजरे को पोषण मिशन अभियान के तहत शामिल किया गया। 500 से अधिक स्टार्टअप बाजार मूल्य श्रृंखला में काम कर रहे हैं। वहीं भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान ने आरकेवीवाई-रफ्तार के तहत 250 स्टार्टअप को साथ लिया है। 66 से अधिक स्टार्टअप को 6.2 करोड़ से अधिक का वितरण किया गया है जबकि 25 स्टार्टअप को आगे वित्तपोषण के लिए मंजूरी प्रदान की गई है।

छिंदवाड़ा में प्राकृतिक खेती फसल विविधीकरण और हो रही मिश्रित खेती

छिंदवाड़ा। जागत गांव हमार

उप संचालक कृषि जितेन्द्र कुमार सिंह द्वारा गत दिवस उद्यानिकी महाविद्यालय के डीन डॉ. विजय पराडकर और जिला स्तरीय टीम के कृषि अधिकारियों व वैज्ञानिकों के साथ जिले के विकासखंड मोहखेड़, बिछुआ और सौंसर के 20 ग्रामों का भ्रमण कर फसल स्थिति का अवलोकन किया गया तथा किसानों से चर्चा कर समसामयिक सलाह दी गई। भ्रमण के दौरान सहायक संचालक कृषि सरिता सिंह, धीरज ठाकुर, नीलकंठ पटवारी, दीपक चौरसिया व सचिन जैन, उप परियोजना संचालक आत्मा प्राची कौतू, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी मोहखेड़, बिछुआ व सौंसर और आत्मा परियोजना के बीटीएम/एटीएम के साथ ही कृषि विभाग का मैदानी अमला और संबंधित ग्रामों के कृषक उपस्थित थे ।

उप संचालक कृषि सिंह ने बताया कि जिले के विकासखंड मोहखेड़ के ग्राम सांवरी, सलैयाकला, टेमनीखुर्द, मेहलारी बाकुल, उमरानाला, पालाखेड़ और महलपुर में किसानों के खेतों का भ्रमण किया गया। ग्राम सांवरी के किसान नितिन रामचन्द्र राव नासेरी के खेत में सात हेक्टेयर में मक्का फसल, 6 हेक्टेयर में ड्रेगन, एक हेक्टेयर में ककडी, 1.5 हेक्टेयर में सागौन और 0.500 हेक्टेयर में आम की फसल लगाई गई है जिसका अवलोकन किया गया। ग्राम सलैया कला के किसान लाखाजी पिता मनक कवरेती के खेत में प्राकृतिक खेती, फसल विविधीकरण और मिश्रित खेती का अवलोकन कर किसानों को आवश्यक जानकारी दी गई। किसान द्वारा जीवामृत, घन जीवामृत, नीमास्त्र, वर्मीकम्पोस्ट, बायोगैस स्लरी का निर्माण कर खेती की जा रही है। ग्राम सलैयाकला के ही किसान बाबूराव मिटठू उइके द्वारा भी प्राकृतिक खेती में आवश्यक सामग्री बनाकर जैसे जीवामृत, घन जीवामृत, नीमास्त्र, वर्मीकम्पोस्ट, बायोगैस स्लरी का निर्माण कर 1.400 हेक्टेयर मे प्राकृतिक खेती की जा रही है। इसी प्रकार वनग्राम मेहलारी बाकुल के किसान श्री उजरलाल टेकाम पिता चंदरलाल के खेत का भ्रमण कर जीवामृत बनाने की विधि और प्रदर्शन कर किसानों को मार्गदर्शन दिया गया।

धान-दलहन की फसल हो रही प्रभावित, किसान चिंतित

विंध्य-बुंदेलखंड में सूखे की आहट!

भोपाल। जागत गांव हमार

दक्षिण-पश्चिम मानसून का आधा मौसम लगभग खत्म होने को है और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के कई जिलों के लोग अभी भी अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। धान और दलहन किसान अपनी मुरझाई फसल को देख रहे हैं। उन्हें सूखे का डर सता रहा है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के 55 वर्षीय किसान मलखान सिंह गौड़ ने अपनी आवाज में एक चिंता के साथ एक एकड़ खेत में धान की सूखती फसल की ओर इशारा करते हुए कहा। पन्ना के बिल्हा गांव के एक आदिवासी किसान गौड़ ने बताया कि अगर बारिश नहीं हुई तो मेरी पूरी धान की फसल खराब हो जाएगी। छोटे पौधे पहले ही पीले हो गए हैं। चिंतित किसान ने कहा कि मेरे पास कुएं या ट्यूबवेल से अपने खेत की सिंचाई करने की सुविधा नहीं है। अगर मेरी धान की फसल खराब हो जाती है तो आगे का खर्च कैसे चलेगा। गौड़ के विपरीत, उनके पड़ोसी सोनेलाल पटेल के पास उनके खेत के पास एक पुराना कुआं है, जिससे वह अपने धान के पौधों को सूखने से बचाने के लिए रोजाना हजारों लीटर निकालते हैं। मैंने डेढ़ (1.5) एकड़ जमीन में धान लगाया है। आधी पौध पहले ही सूख चुकी है। बाकी आधे को मैंने अपने कुएं से पानी देकर किसी तरह जिंदा रखा है। लेकिन यह लंबे समय तक नहीं चल सकता। मेरे जैसे किसान हैं। बारिश का बेसब्री से इंतजार है। सोनेलाल पटेल के पास उनके खेत के पास एक पुराना कुआं है, जिससे वह अपने धान के पौधों को सूखने से बचाने के लिए रोजाना हजारों लीटर निकालते हैं। अगर बारिश नहीं होती है, तो बुंदेलखंड के गौड़ और पटेल जैसे हजारों किसानों को दूर-दराज के शहरों में पलायन करना होगा और जीविकोपार्जन के लिए अपने परिवारों से दूर रहना होगा। अभी के लिए, वे आकाश की ओर देख रहे हैं और अपने धान की नर्सरी सूखने की चिंता कर रहे हैं।

सबसे ज्यादा बारिश सीधी जिले में -51 प्रतिशत

पन्ना जिला बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है। एक पठारी क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश के सात जिलों (चित्रकूट, बांदा, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा और ललितपुर) और मध्य प्रदेश के छह जिलों (छतरपुर, टीकमगढ़, दमोह, सागर, दतिया और पन्ना) में लगभग 69,000 वर्ग किलोमीटर भूमि में फैला हुआ है। केंद्रीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, अब तक इस दक्षिण-पश्चिम मानसून के मौसम में 1 जून से 25 जुलाई तक, पन्ना जिले में माइनस 21 प्रतिशत वर्षा की कमी है। सतना और रीवा के पड़ोसी जिलों में, वर्षा की कमी शून्य से 34 प्रतिशत और शून्य से 43 प्रतिशत कम है। मप्र में सबसे ज्यादा बारिश सीधी जिले में माइनस 51 फीसदी है। हालांकि, मध्य प्रदेश राज्य में कुल मिलाकर 23 प्रतिशत अधिक बारिश हुई है। बुंदेलखंड में स्थिति समान है। अब तक हुई बारिश बहुत कम है। अकेले पन्ना में 100,000 हेक्टेयर भूमि पर धान की खेती की जाती है। धान के अलावा, किसान यहां दलहन और तिल उगाते हैं, लेकिन वे फसलें भी नहीं कर रही हैं इस साल ठीक है।

प्रगतिशील किसान बोले-बारिश के इंतजार में किसान, पिछड़ रही बोवनी

इधर, रीवा जिले के ग्राम नहरो सरैहा ग्राम पंचायत के प्रगतिशील किसान अनिल कुमार मिश्रा ने '**जागत गांव हमार**' से चर्चा के दौरान कहा कि अगर जल्द ही बारिश नहीं हुई, तो किसानों को पलायन करना पड़ेगा। हमारे क्षेत्र के कुछ किसानों ने पहली बारिश ही बोवनी कर दी, लेकिन अब बारिश नहीं होने की वजह से फसल सूख रही है। कई किसानों के खेतों अभी तक हल भी नहीं चल पाया है। उन्होंने कहा कि मैंने ही अच्छी किस्म की धान बाजार से खरीदकर बोवनी की थी, लेकिन पानी नहीं मिलने से सूखने लगी है। यही नहीं, यहां सबसे बड़ी समस्या मवेशी भी बने हुए हैं।

आवश्यकता

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर और मुरैना से प्रकाशित

जागत गांव हमार

कृषि और पंचायत पर आधारित साप्ताहिक समाचार पत्र के लिए जिला, जनपद स्तर पर संवाददाता चाहिए!

संपर्क करें

जबलपुर, प्रवीण नामदेव-9300034195
शहडोल, राम नरेश वर्मा-9131886277
नरसिंहपुर, प्रहलाद कौरव-9926569304
विदिशा, अवधेश दुबे- 9425148554
सागर, अनिल दुबे-9826021098
राहतगढ़, भगवान सिंह प्रजापति-9826948827
दमोह, बंटी शर्मा -9131821040
टीकमगढ़, नीरज जैन -9893583522
राजगढ़, गजराज सिंह मीणा -9981462162
बैतूल, सतीष साहू-8982777449
मुरैना, अवधेश दण्डोतिया -9425128418
शिवपुरी, खेमराज मौर्य-9425762414
भिण्ड- नीरज शर्मा-9826266571
खरगौन, संजय शर्मा-7694897272
सतना, दीपक गौतम-9923800013
रीवा-धनंजय तिवारी-9425080670
रतलाम, अमित निगम-70007141120
झाबुआ-नोमान खान-8770736925

कार्यालय का पता:- लाजपत भवन प्रथम तल, आईसीआईसीआई बैंक के पास, एमपी नगर, ज़ोन-1, भोपाल, मप्र,
संपर्क करें- 07554064144, 9229497393, 9425048589

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादक: अजय कुमार द्विवेदी, स्थानीय संपादक- **अरविंद मिश्र, संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेल:- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)